RNI. No. BIHHIN/2021/80855

सीमांचल की आवाज़

फरवरी 2026 // वर्ष 06 // अंक // 01

₹ 20/-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

जिद सच कहने की...

यूपी बजट 2026-27

योगी का खुला पिटारा

ना पक्ष, ना विपक्ष

सिर्फ निष्पक्ष

क्योंकि हमें जिद है सच कहने की...

सीमांचल की
आवाज़
ज़िद सच कहने की...

मो0 अजहर रहमानी

सम्पादक

सीमांचल की आवाज़

ज़िद सच कहने की...

वर्ष : 06 अंक : 01 पृष्ठ : 52 मूल्य : 20 रुपए

संपादक : मो0 अजहर रहमानी
संपादकीय सलाहकार : अरविंद अग्रवाल
उप संपादक : ब्रजेश झा
मीडिया कार्यकारी : पीयूष कुमार
एक्सक्यूटिव ऑफिसर : गुलाम सरवर मेहंदी
क्रिएटिव हेड : अनवर आलम
कला एवं साहित्य सहयोग : मुरली मनोहर श्रीवास्तव
विशेष सहयोगी : अविनाश कुमार झा
फीचर एडिटर : लोकहर्ष
विशेष संवाददाता : मो0फरहान

ब्यूरो :-
बिहार : मो0असद
दिल्ली : स्वाति सिंह
कोलकाता : रफ्त नसीम
मुंबई : फैज अकरम
यूपी : निशात चौरसिया
पश्चिम बंगाल: मरगुब सालीक
सीमांचल : प्रदीप कुमार
फोटो रिर्सचर: अविनाश चन्द्रा
बिजनेस हेड: मो0 आसिफ रहमानी
विधि सलाहकार : इम्तियाज अली, वरीय अधिवक्ता
सभी पद अवैतनिक और अंशकालिक हैं।

संपादकीय कार्यालय

रोज मार्केट, पश्चिमपाली, कॉलेज रोड़, किशनगंज
Email :- editorseemanchakiawaz@gmail.com
website : seemanchalkiawaz.in
seemanchalkiawaz.com
contact : 06456-291139
Mob. : 9973992786, 9546786806

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक मो0अजहर रहमानी द्वारा 'अक्सा एडवरटाइजिंग', दफ्तरी होम इंटेरियर, पश्चिम पाली, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन एवं जिला किशनगंज - 855108 (बिहार) द्वारा मुद्रित एवं रुईधासा, खानका पुलिस स्टेशन एवं जिला किशनगंज - 855108 (बिहार) से प्रकाशित।

RNI. No. BIHHIN/2021/80855

पत्रिका में छपे समाचार एवं लेखों पर संपादक की सहमति हो अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र किशनगंज होगा।
आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें। किसी भी लेख के लिए रचनाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे। विज्ञापन की सत्यता की जांच पाठक स्वयं अपने स्तर पर कर लें। फोटो - समाचार भी (माध्यम इंटरनेट एवं अन्य स्रोत)
आपको हमारा ये अंक कै सा लगा, हमें जरूर लिखें हमने कोशिश की है कि राज्य, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय और आप से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाए। हमें आपको सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

स्टोरी
सीमांचल की आवाज

08 अमेरिका के साथ एक नई शुरूआत

पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक...

बजट

12 विकसित भारत की नींव रखने वाला साहसिक...

नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार....

राजनीति

16 यूपी बजट 2026-27 योगी का खुला पिटारा

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती...

लेख

35 एप्सटिन फाइल्स शर्म, सन्नाटा और हमारी...

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। जिन कांडों का खुलासा हो रहा है–जिनके वीडियो, दस्तावेज और गवाह सार्वजनिक हो चुके हैं–वे महज अपराध नहीं हैं...

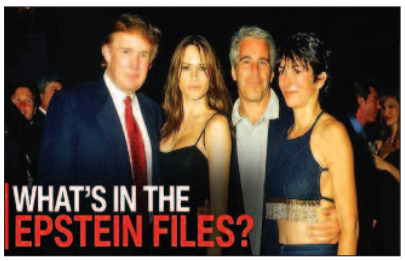

विचार विमर्श

42 ग्रीनलैंड आखिर अमेरिका को क्यों चाहिए

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल लगभग 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर लेकिन आबादी सिर्फ 60 हजार के आसपास। यहां का 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। न घने जंगल, न हाईवे, न चमकते शहर। कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं और कई महीनों तक रात खत्म नहीं होती।

Advertisement Tariff

SEEMANCHAL KI AWAZ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

DISPLAY

REGULAR DISPLAY (B&W)
Rs. 200/- per sq. cm.

REGULAR DISPLAY (COLOUR)
Rs. 400/- per sq. cm.

TENDER NOTICE
Rs. 275/- per sq. cm.

COMPANY /FINANCIAL /AUCTION NOTICE ETC.
Rs. 280/- per sq. cm.

CLASSIFIED

- Change of Name
- Lost & Found
- Wanted Etc.

Upto 20 Words - Rs. 100/-

Every Extra Word - Rs. 5/- Per Word

Mechanical Data

No. of Pages - 52 Columns Per Page - 03 Column
Width of Column 5.1 cm. - Length of Column 29 cm.

Special Position

Last Cover	(Minimum 22 cm.x28 cm.)	75% Extra
Iner Cover	(Minimum 22 cm.x28 cm.)	60% Extra
Special Guaranteed Position/Page 25% Extra		

GIVE MULTIPAL EXPOSURE TO YOUR ADVT.

For Further Details Please Contact

SEEMANCHAL KI AWAZ
RUIDHASA KHANQUAH, KISHANGANJ, BIHAR-855108
Mob. 9973992786, E-mail - editorseemanchalkiawaz@gmail.com

सम्पादकीय

अविश्वास का प्रस्ताव

लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध तो टूट गया और बजट पर चर्चा भी शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की, उससे यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के रिश्ते और अधिक कटु होने वाले हैं। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कहना कठिन है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले विपक्ष ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की थी। आसार यही हैं कि जैसे वह अविश्वास प्रस्ताव कहीं नहीं पहुंच सका था, उसी तरह इस अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई भविष्य नहीं।

चीन के मामले में राहुल गांधी एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वे 2020 में गलवन में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच की झड़प के बाद की घटना पर जनरल नरवणे की जिस पुस्तक के बहाने यह बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चीनी सेना की आक्रामकता से डर गए थे, वह अब तक अप्रकाशित है। इसे प्रकाशक ने भी स्पष्ट कर दिया है और खुद जनरल नरवणे ने भी।

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया। साफ है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चीन के मामले में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक के एक पत्रिका में छपे कथित अंशों के माध्यम से जो कुछ कहना चाह रहे हैं, वह इतना विस्फोटक और सनसनीखेज है कि मोदी सरकार संकट में पड़ जाएगी। यह एक तरह का दिवास्वप्न ही है, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले छह वर्षों में राहुल गांधी के ऐसे बयानों का कहीं कई असर नहीं हुआ। सच तो यह है कि उनके वे बयान भी असरहीन रहे, जिन्हें उन्होंने एटम बम वगैरह की संज्ञा दी थी।

चीन के मामले में राहुल गांधी एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वे 2020 में गलवन में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच की झड़प के बाद की घटना पर जनरल नरवणे की जिस पुस्तक के बहाने यह बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चीनी सेना की आक्रामकता से डर गए थे, वह अब तक अप्रकाशित है। इसे प्रकाशक ने भी स्पष्ट कर दिया है और खुद जनरल नरवणे ने भी।

आखिर ऐसे में राहुल गांधी उनकी कौन सी पुस्तक दिखाते फिर रहे हैं? वे अपने पक्ष को कमजोर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि एक पुराने मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। राहुल कुछ भी कहने की कोशिश करें, यह किसी से छिपा नहीं कि खुद जनरल नरवणे कई बार यह कह चुके हैं कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया था। यह भी सब जानते हैं कि भारतीय सेना की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के कारण ही चीन वार्ता की मेज पर आया था और सीमा पर कई क्षेत्रों में यथास्थिति कायम हुई। यह साफ है कि राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं। उनका एक सूत्रीय एजेंडा राजनीतिक कलह बढ़ाना है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसी का परिचायक है।

-मो0 अजहर रहमानी

भारत-EU समझौता

यूरोप की नई दोस्ती से अमेरिका को कैसे लगा रणनीतिक झटका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाक्य- 'भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता सभी सौदों की जननी है', सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ है। 'जननी जन्म भूमिश्च' को गति देने वाले यूरोप के दो ताकतवर देश हैं- ब्रिटेन और जर्मनी। इस बहुचर्चित श्लोक का पहला वाक्य है, 'मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव।' अर्थात, 'मित्र, धन-धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है।'

> अभियान के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टारमर हाल ही में आधिकारिक दौरे पर बेजिंग पहुंचे। उनके साथ करीब साठ सदस्यों का व्यापार एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। स्टारमर का दौरा इस महीने कई पश्चिमी नेताओं के चीन दौरे के बाद हुआ।

ब्रिटेन और जर्मनी ने जो कुछ किया, उससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से पहले ब्रिटेन और भारत ने जुलाई 2025 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता था। भारत और यूरोपीय देशों की इस साझेदारी से अमेरिकी शुल्क नीति के प्रभाव को कम करने में खासी मदद मिलेगी।

ठीक इसी तरह के अभियान के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टारमर हाल ही में आधिकारिक दौरे पर बेजिंग पहुंचे। उनके साथ करीब साठ सदस्यों का व्यापार एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। स्टारमर का दौरा इस महीने कई पश्चिमी नेताओं के चीन दौरे के बाद हुआ। स्टारमर की यह यात्रा निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असहज करने वाली है। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि चीन के साथ ब्रिटेन के रिश्तों को और बेहतर बनाना जरूरी है। आठ साल में किसी ब्रिटिश नेता का यह पहला चीन दौरा है।

इस वर्ष चार जनवरी को आयरिश प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने चीन का दौरा किया था, 25 जनवरी को फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो बेजिंग पहुंचे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और स्पेन के राजा फेलिप षष्टम ने पिछले साल के आखिर में चीन का दौरा किया था। माना जा रहा है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज फरवरी में चीन का दौरा कर सकते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चीन को कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। इस मामले में उसे भारत इसलिए प्रतिस्पर्धी नहीं लग रहा, क्योंकि चीन भी अमेरिका का सताया हुआ है। सवाल है कि ट्रंप की नीतियों से असहज यूरोपीय शासन प्रमुखों के चीन दौरों से क्या मायने निकलते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बेजिंग दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा, 'चीन दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र है और यह जरूरी है कि हम और ज्यादा बेहतर रिश्ते बनाएं।' इस पर जिनपिंग ने भी स्पष्ट किया कि वे स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने को तैयार हैं।

स्टारमर ने जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को वास्तविक परिणामों के साथ बहुत अच्छी एवं

रचनात्मक बैठक बताया और चीन में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए बेहतर अवसरों पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने मीडिया को संकेत दिया कि शराब की विशेष किस्म पर चीन के शुल्क कम करने और चीन के लिए वीजा-मुक्त यात्रा के मुद्दे पर अच्छी प्रगति हुई है।

अब सवाल यह है कि स्टारमर की इस यात्रा के बाद क्या चीन और यूरोपीय संघ के बीच 'कांप्रिहेंसिव एग्रीमेंट आन इन्वेस्टमेंट' (सीएआइ) को गति मिलेगी? हालांकि, चीन ने बातचीत फिर से शुरू करने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने में दिलचस्पी दिखाई है। स्टारमर का यह दौरा वर्ष 2025 के आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) के बाद हुआ, जिसके बारे में ब्रिटेन के व्यापार और व्यवसाय विभाग ने दावा किया है कि इससे 600 मिलियन पाउंड का तत्काल लाभ हुआ है एवं वर्ष 2018 के बाद पहली बार ब्रिटेन-चीन संयुक्त आर्थिक और व्यापार आयोग (जेटको) की स्थापना हुई है।

दरअसल, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही इसके स्पष्ट संकेत मिलने से उत्साहित होकर ट्रंप विरोधी ताकतें एकजुट होने लगीं। इस महीने की शुरूआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बेजिंग का दौरा किया था। यह घोषणा करने के बाद कि कनाडा कुछ चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क कम करेगा, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर चीन के साथ कनाडा कोई व्यापार समझौता करता है, तो वह कनाडा से आयात पर सौ फीसद शुल्क लगा देंगे।

अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ब्रिटेन के अपने समकक्ष स्टारमर की बेजिंग यात्रा से मजबूती महसूस कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हुई, जब यूरोपीय देश चीन के 1.2 ट्रिलियन डालर के वैश्विक व्यापार अधिशेष से चिंतित हैं। यूरोपीय नेताओं को लगता है कि सस्ता चीनी सामान उनके घरेलू उद्योगों को खोखला कर रहा है। मगर ट्रंप की वजह से इस कड़वे घूंट को भी यूरोपीय नेता मीठा-मीठा मानने लगे हैं।

किअर स्टारमर के दौरे के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह दोनों देशों के साझा हितों के मद्देनजर महत्त्वपूर्ण है और इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्यों के तौर पर चीन और ब्रिटेन के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास में मदद मिलेगी।

सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। वर्तमान परिदृश्य में इनमें से तीन ब्रिटेन, रूस और चीन एक तरफ दिखते हैं। ऐसे में यदि वीटो के उपयोग का विकल्प न हो, तो अमेरिका अलग-थलग पड़ सकता है। मगर यह समझना जरूरी है कि दवा का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारतीय कार निमार्ताओं के शेयरों में पांच फीसद तक की बड़ी गिरावट देखी गई।

इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों को सीधा फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इससे मशीनरी, आप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे यूरोपीय उत्पादों की भारतीय बाजारों में आवक बढ़ेगी। एक सबसे अहम बात यह है कि यूरोप की कई कंपनियों की निर्माण इकाइयां चीन में लगी हैं। ऐसे में नाम भले यूरोपीय संघ का हो, मगर उत्पाद चीन से ही आएगा। शायद इसलिए भी चीन इस समझौते से असहज नहीं है।

दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन इस बात से निराश है कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले प्रस्तावित समझौते तेजी से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भारत-ईयू व्यापार समझौते से अमेरिका को जोर का झटका धीरे से लगा है। अटलांटिक पारीय संधि खतरे में है। अमेरिका के वित्त मंत्री का कहना है कि इस समझौते से यूरोपीय संघ ने यूक्रेन से पहले व्यापार को प्राथमिकता दी है। ट्रंप की दबावकारी नीतियों के कारण अमेरिका वैश्विक मंच पर धीरे-धीरे अलग-थलग पड़ रहा है। न्यूटन के तीसरे नियम की तरह– हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है।

अमेरिका के साथ एक नई शुरूआत

ट्रंप ने टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत किया

मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दशार्ता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है।

पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरूआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक तनाव, आपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की आशंका और अमेरिका के साथ खटपट के नाम रहा। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई बात का बनना बहुत कुछ कहता है।

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह मोदी की विदेश नीति की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की पुष्टि भी है। जब तमाम विश्लेषक यह मान बैठे थे कि ट्रंप 2.0 के दौर में भारत को लगातार दबाव और अपमान झेलना पड़ेगा, उसी दौरान मोदी ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को पलट दिया। यह समझौता दशार्ता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है।

देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात 'द आर्ट आफ द डील' रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे।

स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है।

टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक

नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है।

मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दशार्ता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे 'फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ। भारत-अमेरिका समझौता भी इसी श्रेणी में आता है।

इसमें तनाव घटाने, व्यापार बहाली और रणनीतिक खाई को पाटने जैसे लक्ष्य तो स्पष्ट हैं, लेकिन विवरण अभी शेष हैं। कभी-कभी कूटनीति में दिशा तय करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने विकल्प भी बढ़ाए। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, चीन के साथ सीमित राजनीतिक संवाद और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। इस क्रम में यदि वाशिंगटन भारत के साथ व्यापारिक टकराव जारी रखता तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं।

यही वह बिंदु है, जिसने अमेरिका को अड़ियल रुख से पीटे हटने को विवश किया। इसमें यूरोपीय संघ के साथ समझौते ने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी रुख में परिवर्तन भारत के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि उसके 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारत को एक बड़े बाजार में सीमित कर दिया था। अमेरिकी टैरिफ का 18 प्रतिशत पर आना न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए राहत है, बल्कि यह भारत को फिर से एशियाई प्रतिस्पर्धियों की पंक्ति में खड़ा करता है। इसके चलते वस्त्र, परिधान, रत्न और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को संजीवनी मिलेगी।

चीन से बाहर निकल रही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए भारत फिर से एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। उच्च टैरिफ के चलते जो अवसर भारत के हाथ से फिसल रहे थे, वे फिर से मुट्ठी में आ सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता चीन को भी यह संदेश देगी कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प हैं। हालांकि मोदी की विदेश नीति का मूल तत्व अब भी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह समझौता उस स्वायत्तता को त्यागने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का साधन है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता एक नई शुरूआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसके सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अवसर इसलिए कि यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भारत-अमेरिका संबंध वास्तव में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। चुनौतियां इसलिए कि विवरणों में मतभेद, घरेलू दबाव और ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है।

इसके बावजूद मोदी को श्रेय देना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यह समझौता मोदी के उस दीर्घकालिक सोच का प्रतीक है, जिसमें भारत को एक आत्मविश्वासी, विकल्पों से भरपूर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जाना है। भारत अब किसी भी सौदे में शर्तें तय करने के लिहाज से कहीं बेहतर स्थिति में है।

कई सवाल अब भी बाकी

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से राहत की उम्मीद

पिछले कई महीने से अमेरिका की ओर से लागू शुल्क नीति के कारण जहां दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, वहीं भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश करने की थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उससे यही लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर हित पर आधारित एक समझौता आकार ले सकता है।

ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका-भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत शुल्क को पचास फीसद से घटा कर अठारह फीसद किया जाएगा। दूसरी ओर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणा को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही है, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है।

दरअसल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती और इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी रखी।

यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है। हालांकि भारत और रूस के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसके मद्देनजर यह देखने

अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है।

की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है।

इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। इस मसले पर देश भर में सवाल उठाए गए थे। अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत कृषि जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है, लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं।

इस मसले पर आशंका ट्रंप के उस दावे से उपजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की ओर से काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पाद खरीदने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। अगर भारत कृषि क्षेत्र को भी खोलता है, तो इससे यहां के किसानों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत को अपने किसानों की इस फिक्र को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारत आएंगे, तो देसी फसलों के दाम गिर सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कमजोर होगा और सबसे बड़ा नुकसान छोटे तथा सीमांत किसानों को होगा।

दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणा को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही है, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है।

दरअसल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती और इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी रखी।

यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है। हालांकि भारत और रूस के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है।

इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। इस मसले पर देश भर में सवाल उठाए गए थे। अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत कृषि जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है, लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं।

इस मसले पर आशंका ट्रंप के उस दावे से उपजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की ओर से काफी बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पाद खरीदने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। अगर भारत कृषि क्षेत्र को भी खोलता है, तो इससे यहां के किसानों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत को अपने किसानों की इस फिक्र को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारत आएंगे, तो देसी फसलों के दाम गिर सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कमजोर होगा और सबसे बड़ा नुकसान छोटे तथा सीमांत किसानों को होगा।

विकसित भारत की नींव रखने वाला साहसिक बजट

● डॉ जयंतीलाल भंडारी

यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर बजट को आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है। इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।

गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेंनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं।

निश्चित रूप से वित्तमंत्री इस बजट के माध्यम से युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए है, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। चूँकि इस समय चीन, पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी देश की बाहरी सुरक्षा के खतरे बढ़े हैं, ऐसे में सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है। भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। इतना ही नहीं अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है।

निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। उम्मीद करें कि इस बजट से जहाँ देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू होगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा। उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

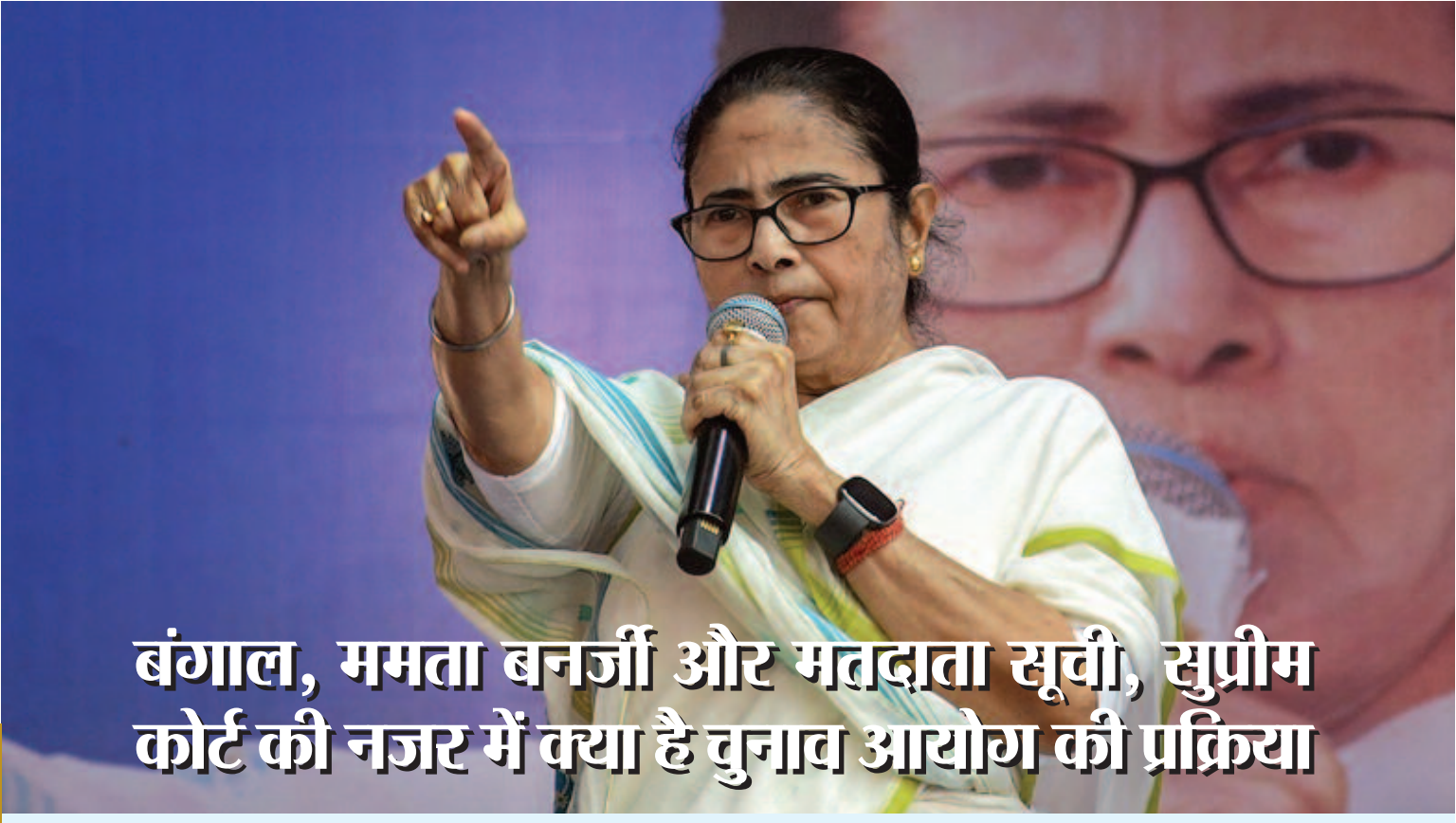

बंगाल, ममता बनर्जी और मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्या है चुनाव आयोग की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश से होकर अब पश्चिम बंगाल में केंद्रित हो गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची से अपात्र लोगों को बाहर करना है, जिनमें स्थान बदलने वाले नागरिक या जिनकी मौत हो चुकी है या फिर गलत तरीके से नाम दर्ज कराने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए इस कवायद को जरूरी माना गया है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, मगर इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और निष्पक्षता का।

विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के तहत मसविदा मतदाता सूची से जितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम बाहर होने के दावे किए जा रहे हैं, उससे आम नागरिकों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इससे संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे।

> **चुनाव में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए इस कवायद को जरूरी माना गया है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी.....**

गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि नागरिकों के नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए और उन्हें इस संबंध में कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को समय पर सूचित करने और उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के पर्याप्त अवसर देने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जाहिर है, अगर पुनरीक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी जाती, तो संभवतः अनावश्यक विवाद खड़े नहीं होते। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए, ताकि इससे नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या तनाव न हो।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि निर्वाचन आयोग को तार्किक विसंगति सूची में नामों का उल्लेख करने के कारणों को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति यह जान सके कि गड़बड़ कहां हुआ है और उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि राज्य में नाम, उपनाम या आयु में गड़बड़ी को लेकर अब तक 1.36 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

इस पर शीर्ष अदालत ने बांग्ला भाषा में बोलचाल का जिक्र करते हुए कहा कि कभी-कभी इसकी वजह से भी नामों की वर्तनी गलत हो जाती है, लेकिन पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में बने रहना जरूरी है। सवाल है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का जो काम निर्वाचन आयोग को खुद अपने स्तर पर शामिल करना चाहिए था, उस संबंध में न्यायालय को निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो, ताकि निर्वाचन आयोग पर आम लोगों का भरोसा पूरी तरह कायम रहे।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम

बजट में वर्ष 2031 तक जीडीपी के मुकाबले ऋण अनुपात को 50 प्रतिशत तक कम करने की राह तैयार की गई है। यह राजकोषीय घाटे को घटाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। घाटे को नियंत्रित रखने के बावजूद सरकार ने विकास गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी उदारता दिखाई है।

● जी एन वाजपेयी

केंद्रीय बजट भारत सरकार की सबसे व्यापक वार्षिक आर्थिक गतिविधियों में से एक है। यह कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दशार्ता है। कराधान और व्यय नीति को निर्धारित करता है। कल्याणकारी एवं विकास संबंधी योजनाओं पर खर्च का खाका तैयार करता है। इसकी नीतियां जीडीपी वृद्धि, निवेश और रोजगार से लेकर महंगाई के रुझान को भी प्रभावित करती हैं। गत रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया, वह भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

वैसे तो बजट एक वार्षिक आयोजन है, लेकिन इस बजट के मूल में एक दूरगामी लक्ष्य है और वह है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के लिए बुनियाद को मजबूत बनाना। इस बजट में भारत की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने एवं विकसित भारत को मूर्त रूप देने वाले पहलुओं का समावेश है। इसमें वित्तीय नीति, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय, विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्र, एमएसएमई और उद्यमिता समर्थन, कराधान उपाय और सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि की आवश्यकताओं को भलीभांति चिह्नित कर उनके लिए अपेक्षित उपाय किए गए हैं।

वैश्विक अनिश्चित माहौल में वित्त मंत्री ने विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। बजट में वर्ष 2031 तक जीडीपी के मुकाबले ऋण अनुपात को 50 प्रतिशत तक कम करने की राह तैयार की गई है। यह राजकोषीय घाटे को घटाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। घाटे को नियंत्रित रखने के बावजूद सरकार ने विकास गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी उदारता दिखाई है।

बजट ब्याज के बोझ को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को भी संतुलित करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर जारी है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कई महत्वाकांक्षी नई परियोजनाओं का भी एलान किया गया है। इनमें सात हाई स्पीड रेल कारिडोर प्रमुख हैं। इनके अलावा नए डेडिकेडेट फ्रेट कारिडोर का निर्माण, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण, एक तटीय कार्गो प्रमोशन योजना और सात सिटी इकोनमिक जोन भी शामिल

हैं। रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र भी बजट की प्राथमिकता के केंद्र में है। इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में सेमीकंडक्टर मिशन, घरेलू चिप निर्माण, आपूर्ति शृंखला में लचीलेपन और प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य शृंखलाओं को आकार देने पर ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा उत्पादन और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। रेयर अर्थ कारिडोर की पहल रेखांकित करती है कि भविष्य की योजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।

बायोफार्मा शक्ति मिशन और कार्बन कैप्चर, उपयोग, और भंडारण जैसी पहल भी सरकार के रणनीतिक सोच को रेखांकित करती हैं। सैकड़ों पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुत्थान और डेडिकेटेड रासायनिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से सरकार इकोसिस्टम संचालित ढांचे पर दांव पर लगा रही है। यह 'वाल्यूम प्रोड्यूसर' से 'वैल्यू प्रोड्यूसर' यानी मात्रात्मक उत्पादक से नवाचार प्रेरित गुणात्मक उत्पादक बनने की योजना पर काम कर रही है।

अगर 2030 तक देश को सात ट्रिलियन (लाख करोड) डालर की इकोनमी बनाना है तो ऐसा परिवर्तन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। बजट में छोटे उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बड़े कोष की स्थापना का भी प्रविधान है। इसका उद्देश्य उद्यमों तक पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना और आर्थिकी की रीढ़ को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी, बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से तरलता में सुधार जैसे तमाम उपाय भी उद्यमों के अनुकूल हैं।

बजट ने कई सामाजिक आयामों का भी ध्यान रखा है। जैसे कृषि को 1.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, चंदन, काजू और कोको के लिए सार्थक उपाय किए गए हैं। साथ ही पारंपरिक अनाज फसलों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है। भारत विस्तार एआइ किसानों को मौसमी जानकारियां, मिट्टी की सेहत और बाजार कीमतों को एकीकृत करके आवश्यक मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होगा। इसकी सेवाएं कई भाषाओं में होंगी।

लाभार्थी दीदी की सफलता के बाद 'शी-मार्ट योजना ग्रामीण महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है। चिकित्सा हब की स्थापना भारत को एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, 1.5 लाख विशेष कर्मियों को प्रशिक्षित करना हेल्थकेयर सेवाओं की बढ़ती मांग के अनुरूप ही है। उच्च शिक्षा से संबंधित एक नई समिति शैक्षणिक ढांचे और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का काम करेगी। पर्यटन को प्राथमिकता में रखते हुए 50 महत्वपूर्ण गंतव्यों में प्राचीन पुरातात्विक स्थलों के कायाकल्प और विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण की योजना से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन आर्थिकी की संभावनाओं को भुनाना आसान होगा।

कराधान ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सुगमता के तमाम उपाय अवश्य किए गए हैं। कुछ आलोचकों को यह अखरेगा कि बजट में क्रांतिकारी घोषणाएं नहीं की गईं। इस पर यही कहना अधिक उचित होगा कि वित्त मंत्री ने कोई तात्कालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक मजबूती को वरीयता दी। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता के संकेत दे रही हो, लेकिन वैश्विक स्थितियां व्यापक रूप से अनिश्चित एवं अस्थिर बनी हुई हैं। ऐसे फिसलन भरे परिदृश्य में मजबूती देने वाले ऐसे ही बजट की आवश्यकता थी कि भारत के कदम फिसलें नहीं और वह सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चमकता रहे।

(लेखक सेबी एवं एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

यूपी बजट 2026-27

योगी का खुला पिटारा

किसानों में खुशी की लहर, मिलीं ये बेहतरीन सौगातें

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। ₹नव निर्माण के नौ वर्ष₹ की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दशार्ता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में

उन्होंने बताया कि 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में 'जन विश्वास सिद्धांत' लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजनाः वाराणसी रीजन चयनित

केन्द्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को 'इकोनॉमिक हब' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी

उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरूआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

ऋण प्रबंधन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29.3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27.9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33.4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुनः 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

नई योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय संरचना की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233.18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928.12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305.06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401.76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910.76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यूपी के बजट में किसानों के लिए क्या ?

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपये से अधिक के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है. यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपये से भी 90,802 करोड़ रुपये अधिक है.

- पेराई सत्र 2025-2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि की गयी है. इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा.
- रबी विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेंहू का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

किसान एग्री हब बन रहा

लखनऊ के गोमतीनगर में किसान एग्री हब का निर्माण चल रहा है. कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के कार्यक्रम चल रहे.

फ्री विद्युत आपूर्ति दी जा रही

नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को 1 अप्रैल, 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है.

ये लाभ भी मिले किसानों को

1. वर्ष 2025-2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 19 दिसंबर, 2025 तक 10,257 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 1 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया.
2. वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपये 600 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर, 2025 तक 205 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया.
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017-2018 से 2024-2025 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.
4. वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है.
5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माह दिसंबर, 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी.

यूपी बजट 2026-27

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए शेरो शायरी के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने जो कार्य किये हैं, उससे स्थिति में कितना बदलाव हुआ है। खन्ना ने भाषण में शेर-ओ-शायरी का भी भरपूर उपयोग किया। वित्त मंत्री ने यूपी के हर काम की तारीफ करते हुए शायरी पढ़ी तो पिछली सरकारों पर भी तंज कसा।

खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सर्वत्र सराहना का जिक्र किया। योगी सरकार के हर काम की तारीफ की और शेर पढ़ा...

काबिले तारीफ है, अंदाज एक-एक काम का
गा रहा है गीत यूपी, योगी जी के नाम का

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है। खन्ना ने अपने नजरिए से योगी आदित्यनाथ का संकल्प सुनाया...

यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है
दिया जला के रोशनी कर दूं, जहां अंधेरा है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के त्वरित विस्तार पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। उन्होंने सरकार के कार्यों और मेहनत का जिक्र कुछ यूं किया...

सितारा बनके आसमां में वही चमकते हैं
डुबो देते हैं जो अपने आपको पसीने में

सुरेश खन्ना ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा पर भी तंज कसा। फिर अपनी सरकार में इन धरोहरों की बदली स्थिति का भी जिक्र किया। बोले कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य किया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की भी जानकारी दी।

ये अलग बात है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है।
गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं।।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर्वसमावेशी विजन और महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों व समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की चिंता का भी जिक्र किया। सीएम योगी की दूरदृष्टि, दृढ़संकल्प और अहर्निश श्रम से संभव हो रहे कार्यों पर उन्होंने शेर पढ़ा...

बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है,
गम की हर शाम दबे पांव चली जाती है।
वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में,
पर बदलने में वक्त, जिंदगी लग जाती है।।

अपने भाषण के आखिरी शेर में उन्होंने प्रदेश के सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज का जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार की कार्यशैली जीवन दर्शन से अनुप्राणित है, उन्हें अपनी भावनाओं को कुछ यूं शब्द दिया...

बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूं फलसफा मैं हर किसी के लिए।
पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जियें आप फकत अपनी ही खुशी के लिए।।

दिव्यांगजन पेंशन बढ़ी तीन गुना से अधिक

यूडीआईडी कार्ड से लेकर पेंशन तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन

योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण को सामाजिक न्याय की धुरी बनाते हुए पेंशन, सहायता योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। सरकार की पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध व्यवस्था के चलते आज प्रदेश में कोई भी पात्र दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं है। विधानपरिषद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और जो भी पात्र है, उसे शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा।

तीन गुना से अधिक बढ़ी दिव्यांगजन पेंशन, सीधा खाते में भुगतान

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2017 से पूर्व दिव्यांग पेंशन मात्र 300 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह पेंशन पात्र लाभार्थियों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती।

यूडीआईडी कार्ड से लेकर पेंशन तक पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में 31 जनवरी 2026 तक 24,414 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

पात्रता के आधार पर लाभ, यूडीआईडी कार्ड से स्वतः पेंशन नहीं

मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि यूडीआईडी कार्ड धारक सभी दिव्यांगजन स्वतः पेंशन के पात्र नहीं होते। पेंशन के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता, ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से कम वार्षिक आय तथा अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न लेना अनिवार्य है। आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है, जिसकी जांच जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है।

वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,356 पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन, 153 कुष्ठावस्था पेंशन और 321 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी पात्र लाभार्थी लंबित नहीं है।

दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने दो टूक कहा कि विभाग में दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी स्तर पर शिकायत मिलती है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो दिव्यांगजन स्वयं कार्यालय नहीं आ सकते, उनके घर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाए।

विशेष विद्यालयों और पदोन्नति प्रक्रिया पर भी सदन को दी जानकारी

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विशेष विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चयनित शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं और इस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मंत्री कश्यप ने यह भी स्पष्ट किया कि वितरण कार्यक्रमों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने की प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश , पर्व-त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली, महाशिवरात्रि और रमजान सहित विभिन्न पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 02 से 04 मार्च तक होली का पर्व मनाया जाएगा। ब्रज क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में होलिकोत्सव के दौरान हर्ष और उल्लास का माहौल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करायें कि शोभायात्राओं में उपद्रवी तत्वों की घुसपैठ किसी भी स्थिति में न होने पाए। रंग में भंग डालने वालों, उन्माद फैलाने वालों एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सभी मंडलों, पुलिस जोन, रेंज एवं जनपदों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में पर्व-त्योहारों के दौरान घटित घटनाओं से सीख लेते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सतर्कता, निगरानी एवं प्रबंधन को और अधिक मजबूत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होलिका दहन केवल परंपरागत स्थलों पर ही कराया जाए, सड़क के मध्य किसी भी स्थिति में दहन न किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सतत निगरानी रखी जाए। आगामी महाशिवरात्रि, होली, रमजान, माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं, जनगणना तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध समय से सुनिश्चित किए जाएं।

महाशिवरात्रि के अवसर पर जलार्पण हेतु निकलने वाले कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहें। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस संबंध में पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर खीरी एवं बाराबंकी के जिलाधिकारियों से महाशिवरात्रि पर प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 14 एवं 15 फरवरी को प्रमुख शिवधामों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन, यातायात, पार्किंग, महिला सुरक्षा तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें 247 सक्रिय रहें। मंदिर परिसरों में तैनात पुलिस कार्मिक श्रद्धालुओं से मर्यादित व्यवहार करें तथा पर्याप्त संख्या में महिला कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यातायात जाम के प्रमुख कारकों को चिन्हित कर उनके स्थायी समाधान सुनिश्चित किए जाएं। अस्थायी व्यवस्थाओं के स्थान पर दीर्घकालिक एवं व्यवहारिक उपाय लागू किए जाएं, ताकि आमजन को अनावश्यक असुविधा न हो।

धर्मस्थलों पर ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए कि उनकी आवाज किसी भी स्थिति में परिसर से बाहर न जाए। पूर्व में ऐसी गतिविधियों के कारण कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अतः नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों में रात्रि 10 बजे के उपरांत डीजे, साउंड सिस्टम अथवा तेज ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मस्थलों के आसपास भिक्षावृत्ति की गतिविधियों में वृद्धि संज्ञान में आई है। इस पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा संबंधित व्यक्तियों के यथोचित पुनर्वास की योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने 108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम एवं कार्यक्षमता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अवैध, जहरीली एवं नकली मदिरा के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधित विभाग निरंतर अलर्ट रहें। ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना मिलते ही त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध विशेष सतर्कता बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षाएं नकलविहीन कराई जाएं तथा परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी अवधि में रमजान माह भी प्रारंभ होगा तथा संभावित रूप से 21 मार्च को ईद का पर्व मनाया जाएगा। धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखा जाए। किसी भी स्थिति में कोई नई परंपरा प्रारंभ न की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मार्च से वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होंगे, इसके उपरांत राम नवमी का पर्व आएगा। इन सभी आयोजनों की तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि आगामी दिनों में जनगणना का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए सभी जिलाधिकारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं जवाबदेही के साथ करे।

सीएम योगी की बाबरी ढांचे का सपना देखने वालों से दो टूक, कभी नहीं आने वाला कयामत का दिन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे का सपना देखने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है, जो लोग इसका सपना देख रहे हैं, सड़-गल जाएंगे। हिंदुस्तान में कायदे में रहने वाले फायदे में रहेंगे। अगर कोई कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। कानून तोड़ने वाले का रास्ता कहीं और नहीं, सीधे जहन्नुम की तरफ ले जाता है। मुख्यमंत्री ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि यह डबल इंजन सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जो बोलती है, वह करके दिखाती है और जितना करती है, उतना ही बोलती है। हमने कहा कि रामलला आएंगे...। अब मंदिर भी बन गया है। हम विरासत को सम्मान देते हुए भारत व सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे। पीएम मोदी ने 25 नवंबर को अयोध्या में सनातन के प्रतीक श्रीराम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, यह ध्वज सदा भारत व सनातन के गौरव को आगे बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री हिंद केसरी ब्रह्मलीन महंत बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीराम जानकी मंदिर, दुल्हदेपुर कुटी (बाराबंकी) में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्री रामार्चा पूजन में सम्मिलित हुए। सीएम ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं व उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कहा कि बाराबंकी में जल्द ही विकास प्राधिकरण प्रारंभ होगा।

सीएम की दो टूक, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्ष पश्चात यह गौरवशाली क्षण आया। इतने वर्षों में अनेक राजा-महाराजा आए। 1952 के बाद से अनेक सरकारें बनीं, लेकिन किसी से मन में यह नहीं आया कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर निर्माण हो। राम सबके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं। जब संकट आता है तो उन्हें राम याद आते हैं, बाकी समय राम को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम भी भूल चुके हैं,

यह देश कभी कमजोर नहीं था

सीएम योगी ने कहा कि यह देश कभी कमजोर नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। उन्होंने 2017 के पहले यूपी में फैली असुरक्षा का जिक्र किया। कहा, हर तीसरे-चौथे दिन किसी न किसी जनपद व शहर में कर्फ्यू-दंगे होते थे। परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्यास्त होते यदि घर नहीं आया तो घरवाले सशंकित रहते थे। गरीबों की जमीन पर कब्जा हो जाता था। सैकड़ों पहलवान तैयार करने वाले बाबा हरिशंकर दास का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि श्रीराम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ। बाबा जी को गोली मार दी गई, लेकिन सरकार बदलते ही यूपी में सारी अराजकता गायब हो गई। 2013 कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष माघ मेला में अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या व वाराणसी में पहले लाखों श्रद्धालु आते थे, अब वह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। 2024-25 में 122 करोड़ श्रद्धालु यूपी के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने आए। महाकुम्भ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए, यह संख्या बताती है कि यूपी में अब सुरक्षा और सुविधा है। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज सुरक्षा का अहसास कर लेगा, व्यापारी सुरक्षित होगा तो उत्तर से दक्षिण तक सेतुबंध के रूप में कार्य करेगा।

अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है। रामभक्तों पर गोली चलाने वालों और रामकाज में बाधक रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। बाबरी ढांचे का सपना देखने वालों को योगी ने चेताया कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कानून तोड़ने वालों का रास्ता जन्नत नहीं, सीधे जहन्नुम की तरफ जाएगा।

पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पहले यूपी में वेतन देने का पैसा नहीं था, लेकिन आज पैसे का उपयोग हर तबके के हित के लिए हो रहा है। छात्रों को बिना भेदभाव छात्रवृत्ति दी जा रही है। यूपी में अच्छे संस्थान खुल रहे हैं, हर तीर्थ स्थल का विकास हो रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। कानून को ठेंगा दिखाने वालों को ऐसा मजा चखाएंगे कि सात पीढ़ियां याद करेंगी। सीएम ने विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि 8-9 साल पहले तक जो पैसा भ्रष्टाचार में खर्च होता था, वह आज विकास में खर्च हो रहा है।

यूपी अब 'बीमारू' नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का मजबूत राज्य

सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। यूपी अब 'बीमारू' नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का मजबूत राज्य बनकर उभरा है। गांव की बेटी, सबकी बेटी मानते हुए सरकार बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक की पढ़ाई, शादी आदि की जिम्मेदारी उठा रही है। दिव्यांगजन, वृद्धजन व निराश्रित महिलाओं के रूप में 1.6 करोड़ परिवारों को सरकार 12 हजार रुपये सालाना की पेंशन दे रही है। यूपी में 15-16 करोड़ लोग राशन की सुविधा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक 5.46 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए पांच लाख रुपये निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा वाले गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार बिना भेदभाव सबके विकास के लिए कार्य कर रही है।

संत स्वभाव के थे बाबा हरिशंकर दास जी महाराज

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा हरिशंकर दास जी महाराज संत स्वभाव के थे। वह हनुमान जी के परमभक्त और पहलवानी में पारंगत थे। उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी में सिद्धि थी। उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र में बरस रहा है। भगवान लोधेश्वर महादेव का पवित्र

दुनिया भर से सनातन, भारत-भारतीयता पर प्रहार

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हर भारतीय का दायित्व सकारात्मक सोच के साथ भारत का विकास होना चाहिए। सभी भारतीय मिलकर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के लिए कार्य करें। जीवन का संकल्प होना चाहिए कि हमारा देश वैभवशाली व विकसित हो। हर संत की साधना देश, धर्म के लिए होती है और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। एक शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा। भारत और सनातन एक-दूसरे के पूरक हैं, इसे अलग करके नहीं रखा जा सकता। वर्तमान में दुनिया भर से सनातन, भारत-भारतीयता पर प्रहार हो रहे हैं। अंदर-बाहर से होने वाले इन प्रहारों से सचेत रहना होगा। जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, विकसित भारत की संकल्पना पचती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग साजिश के लिए बिक कर कार्य कर रहे हैं। हमें यह दुष्प्रवृत्ति रोकनी होगी।

धाम इस जनपद में है। इस जनपद ने हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू को जन्म दिया था। यहां बाबा लोधेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनेगा। पैसा दिया जा चुका है, कार्य प्रारंभ होने वाला है। केडी बाबू की हवेली बिक रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि वह बिकेगी नहीं, बल्कि सरकार उसका खर्चा देगी। हवेली में उनका स्मारक बनेगा और यहां खेल की नई एकेडमी बनाएंगे। पीएम मोदी ने यहां के प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा को पद्म पुरस्कार देकर किसानों के परिश्रम व पुरुषार्थ को सम्मानित किया है।

एससीआर में आएगा बाराबंकी जनपद

सीएम योगी ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है। परिक्रमा मार्ग बनेगा तो यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा। रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होगी। स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के अंतर्गत बाराबंकी जनपद भी है। यहां विकास के बड़े कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। रामसनेही घाट के पास बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, बाराबंकी के नौजवान को यहीं रोजगार मिलेगा। पौराणिक काल से इसका गौरवशाली अतीत रहा है। जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और डबल इंजन सरकार भविष्य को और भी गौरवान्वित क्षण के रूप में बदलने का कार्य करने जा रही है।

इस अवसर पर खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद शर्मा, प्रभारी मंत्री सुरेश राही, डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल, विधायक दिनेश रावत, साकेंद्र प्रताप वर्मा, विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह, अंगद सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राम सिंह वर्मा, उप्र अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, कार्यक्रम आयोजक हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंत बलराम दास समेत अनेक संत भी मौजूद रहे।

विमान हादसों में नेताओं की असमय विदाई

संयोग, चयन-पूर्वाग्रह या व्यवस्था की गहरी कमजोरी?

● डेस्क

भारत की राजनीतिक यात्रा बार-बार आकाशी हादसों की भेंट चढ़ती रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती विमान दुर्घटना ने एक बार फिर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पांच लोगों की मौत के साथ राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ, जिसकी भरपाई केवल संवेदनाओं से संभव नहीं। यह पहला मामला नहीं है—संजय गांधी (1980), माधवराव सिंधिया (2001), वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (2009) जैसे उदाहरण बताते हैं कि उच्च पदस्थ नेताओं की अकाल मृत्यु बार-बार एक ही प्रश्न खड़ा करती है: क्या विमान हादसे महज संयोग हैं, किसी साजिश का परिणाम, या फिर हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी?

भारतीय राजनीति में हवाई यात्रा अब सुविधा नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुकी है। चुनावी दौर में एक प्रत्याशी औसतन 120झ150 सभाएँ करता है; सप्ताह में 40झ50 उड़ानें असामान्य नहीं। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में बारामतीझमुंबईझदिल्ली के बीच निरंतर आवाजाही समय की मजबूरी है। ऐसे में चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर नेताओं की पहली पसंद बनते हैं।

लेकिन यही विकल्प सबसे अधिक जोखिमपूर्ण भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट और चार्टर्ड विमानों की दुर्घटना दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कई गुना अधिक है। कारण स्पष्ट हैं—सीमित पायलट अनुभव, पुराने विमानों का उपयोग, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, अस्थायी हेलीपैड और डीजीसीए की अपेक्षाकृत ढीली निगरानी।

अजित पवार की दुर्घटना हो या वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसा, या माधवराव सिंधिया का चार्टर्ड विमान—प्रारंभिक और अंतिम जाँचें बार-बार पायलट त्रुटि, तकनीकी विफलता या प्रतिकूल मौसम की ओर इशारा करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि नेता रेल या कमर्शियल फ्लाइट से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे चुनावी प्रचार की गति से मेल नहीं खा पातीं।

चुनावी मौसम में यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सैकड़ों हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान किराये पर लिए गए। कई मामलों में रखरखाव प्रमाण-पत्रों, पायलट रेस्ट-नॉर्म्स और हेलीपैड मानकों की अनदेखी सामने आई। राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले तथाकथित 'पॉलिटिकल पैकेज'—कम कीमत, पुराने मॉडल—जोखिम को और बढ़ाते हैं।

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में केवल नेता ही विमान हादसों में मरते हैं? उत्तर है—नहीं। भारत में हर वर्ष सैकड़ों छोटे विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। लेकिन मीडिया का फोकस हाई-

प्रोफाइल चेहरों पर टिक जाता है। यही चयन-पूर्वाग्रह है—जो दिखता है, वही पूरा सत्य लगने लगता है।

वैश्विक स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखती है। अमेरिका में जॉन एफ. कैनेडी जूनियर, यूरोप में पोलैंड के राष्ट्रपति लेह काचिंस्की, अफ्रीका और रूस में राष्ट्राध्यक्षों की हवाई दुर्घटनाएँ—हर जगह साजिश की थ्योरी पहले आती है, तथ्य बाद में। जबकि अंतरराष्ट्रीय विमानन आंकड़े बताते हैं कि जनरल एविएशन में अधिकांश दुर्घटनाएँ मानवीय भूल और सिस्टम फेलियर का परिणाम होती हैं। दुर्भाग्य से मीडिया की सनसनीखेजी इन हादसों को 'राजनीतिक षड्यंत्र' में बदल देती है। इससे न केवल जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास भी गहराता है।

समस्या मूलतः व्यवस्थागत है। डीजीसीए के पास चार्टर्ड विमानों की निगरानी के लिए संसाधन सीमित हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश मौजूद हैं, पर उनका प्रवर्तन कमजोर है। पायलट प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और अस्थायी हेलीपैड—तीनों में गंभीर सुधार की जरूरत है।

अब समय आ गया है कि शोक के बाद भूलने की परंपरा छोड़ी जाए। इसके लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम अनिवार्य हैं। सबसे पहले, राजनेताओं के लिए एक डेडिकेटेड एयर विंग विकसित किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय वायुसेना का वीवीआईपी बेड़ा संचालित होता है, जिसमें आधुनिक हेलीकॉप्टर, उन्नत जीपीएस-रडार सिस्टम और अत्यधिक प्रशिक्षित पायलट हों। दूसरा, चुनावी मौसम में उपयोग होने वाले चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए सख्त राष्ट्रीय मानक तय किए जाएँ और उनकी रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए, ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। तीसरा, नेताओं की अत्यधिक यात्रा को कम करने के लिए वर्चुअल रैलियों, डिजिटल संवाद और तकनीक आधारित प्रचार को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अनावश्यक उड़ानों का दबाव घटे। चौथा, पायलट प्रशिक्षण, उड़ान से पहले तकनीकी जाँच और विमान रखरखाव पर जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली प्राइवेट कंपनियों पर कठोर दंड लगाया जाए। अंततः, मीडिया के लिए भी जिम्मेदार रिपोर्टिंग संबंधी स्पष्ट गाइडलाइंस तय हों, ताकि हर विमान हादसे को साजिश में बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।

नेताओं की असमय मृत्यु केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती—वह सत्ता संतुलन, नीतिगत निरंतरता और लोकतांत्रिक भरोसे को भी चोट पहुँचाती है। अजित पवार, वाई.एस.आर. या संजय गांधी—हर हादसा हमें चेतावनी देता है। विमान दुर्घटनाएँ साजिश नहीं, बल्कि लापरवाही, दबाव और कमजोर व्यवस्था का परिणाम हैं। अगर आज सुधार नहीं हुआ, तो कल शोक केवल दोहराया जाएगा।

लोकतंत्र के पायलटों को सुरक्षित आकाश चाहिए—यह केवल एक भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि समय की ठोस माँग है। बार-बार होने वाले विमान और हेलीकॉप्टर हादसे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि समस्या किसी एक नेता, एक दल या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक यात्रा-संस्कृति और विमानन व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरी से जुड़ी है। जब लोकतंत्र के प्रतिनिधि असुरक्षित साधनों से यात्रा करने को मजबूर होते हैं, तो उसका दुष्परिणाम केवल एक परिवार या दल नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र को भुगतना पड़ता है।

नेताओं की असमय मृत्यु सत्ता में शून्य, नीतियों में अस्थिरता और जनता के भरोसे में दरार पैदा करती है। इसके साथ ही साजिश की अफवाहें लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कमजोर करती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर हादसे के बाद संवेदना व्यक्त कर आगे बढ़ जाने के बजाय, ठोस सुधारों को राजनीतिक इच्छा-शक्ति से जोड़ा जाए। सुरक्षा मानकों में ढील, निगरानी की कमजोरी और जल्दबाजी में की गई उड़ानें किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती हैं।

यदि भारत सचमुच मजबूत और स्थिर लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने प्रतिनिधियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। सुधार आज होंगे, तभी कल शोक की पुनरावृत्ति रुकेगी। सुरक्षित आकाश केवल नेताओं के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निरंतर उड़ान के लिए अनिवार्य है।

इस्लामिक जगत में बदलते समीकरण

भारत को सतर्क रहना होगा

इस बदलते परिदृश्य में एक धारा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच उभरती निकटता के रूप में दिखाई देती है, जिसे 'इस्लामिक नाटो' भी कहा जा रहा है।

● आनंद कुमार

पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना इस समय एक गहरे, लेकिन अपेक्षाकृत शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसके मूल में विचारधारा से अधिक भू-राजनीतिक यथार्थ, आर्थिक गणनाएं और क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। अमेरिका की घटती सुरक्षा भूमिका, यूरोप की आंतरिक विभाजित स्थिति और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों ने क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी स्वयं संभालने के लिए प्रेरित किया है।

लंबे समय तक पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व और गारंटी पर आधारित रही, किंतु ट्रंप के कार्यकाल के बाद से अमेरिका की नीति अधिक लेन-देन आधारित और अनिश्चित होती गई है। इससे पारंपरिक सहयोगी देशों को यह महसूस होने लगा कि संकट के समय अमेरिकी हस्तक्षेप स्वतःस्फूर्त नहीं रहेगा। यूरोप भी यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट के कारण इस क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय शक्तियां वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तलाश में हैं। इस बदलते परिदृश्य में एक धारा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच उभरती निकटता के रूप में दिखाई देती है, जिसे 'इस्लामिक नाटो' भी कहा जा रहा है।

पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग रखता आया है, किंतु हालिया वर्षों में इस संबंध को व्यापक रणनीतिक ढांचे में बदलने का प्रयास तेज हुआ है। उसकी कोशिश है कि सऊदी संसाधनों और तुर्किये की रक्षा तकनीक के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा समूह बनाया जाए, जो अमेरिका पर निर्भरता कम कर सके। हालांकि इस प्रस्तावित धुरी की मजबूती उतनी नहीं है, जितनी उसकी राजनीतिक बयानबाजी से प्रतीत होती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और उसकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता सीमित होती जा रही है। भारत के साथ उसका संघर्ष केवल भू-क्षेत्रीय

नहीं, बल्कि वैचारिक भी है, जिसे उसकी सैन्य स्थापना अब भी 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' के रूप में जीवित रखे हुए है।

इसी वैचारिक ढांचे के माध्यम से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में समर्थन जुटाने की कोशिश करता रहा है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर उसे बार-बार यह एहसास हुआ है कि मजहबी एकजुटता अपने आप में स्थायी रणनीतिक समर्थन की गारंटी नहीं देती। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को विविधीकृत कर रहा है। उसके अमेरिका, चीन, भारत और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समानांतर संबंध हैं। भारत में उसके बड़े आर्थिक हित हैं। तुर्किये भी नाटो का सदस्य रहते हुए स्वतंत्र क्षेत्रीय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस प्रस्तावित धुरी में अंतर्विरोध पैदा होते हैं। सऊदी और तुर्किये दोनों ही मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की आकांक्षा रखते हैं, जो उन्हें सहयोगी से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। शायद इसीलिए उसने सऊदी और पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के समानांतर एक दूसरी रणनीतिक साझेदारी भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच उभर रही है। यह साझेदारी साझा सुरक्षा चिंताओं, तकनीकी क्षमताओं पर आधारित है। रक्षा, खुफिया, समुद्री सुरक्षा, साइबर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में यह सहयोग धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। यूएई का दृष्टिकोण वैचारिक नेतृत्व के बजाय स्थिरता, प्रतिरोधक क्षमता और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। यमन से लेकर अफ्रीका के हार्न क्षेत्र तक यूएई ने यह दिखाया है कि वह अपने सुरक्षा हितों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे पारंपरिक सहयोगियों से अलग रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। इजरायल के साथ सामान्यीकरण ने यूएई को क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक नई स्थिति प्रदान की है। भारत के लिए यह साझेदारी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। जहां नई दिल्ली पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक जगत में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों को लेकर सतर्क है, वहीं वह इजरायल के साथ दशकों से चले आ रहे संबंधों को यूएई जैसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के साथ जुड़ने का भी अवसर देख रही है।

हाल में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग पर आशय पत्र इसी दिशा में एक संकेत है। इस समीकरण का विस्तार पूर्वी भूमध्यसागर तक दिखाई देता है, जहां भारत, इजरायल, ग्रीस और साइप्रस के बीच बढ़ता संवाद तुर्किये की समुद्री आक्रामकता और व्यापार मार्गों की सुरक्षा से जुड़ा है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे प्रयास इस रणनीतिक नेटवर्क को आर्थिक आधार भी प्रदान करते हैं। एक ओर ऐसा ढांचा है जो वैचारिक अपील और प्रतीकात्मक शक्ति पर निर्भर करता है, दूसरी ओर एक ऐसा समीकरण है, जो आर्थिक मजबूती, तकनीकी सहयोग और साझा सुरक्षा पर आधारित है।

पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुध्रुवीय, आत्मनिर्भर और क्षेत्रीय रूप से संचालित ढांचे की ओर अग्रसर है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से सुसंगत हैं, वे इस नए परिदृश्य में बेहतर स्थिति में होंगे। जो केवल वैचारिक नारों और प्रतीकात्मक गठबंधनों पर निर्भर हैं, वे शायद ध्यान आकर्षित कर लें, लेकिन स्थायी शक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर भी भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में एसोसिएट फेलो हैं)

आखिर कब निकाले जाएंगे घुसपैठिए?

केवल चुनाव के समय ही चर्चा करना ठीक नहीं

पूर्वोत्तर और बंगाल में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली तक में बस गए हैं। यदा-कदा कुछ राज्य सरकारें उनकी पहचान करने का अभियान चलाती हैं, लेकिन अभी तक कोई अभियान प्रभावी नहीं सिद्ध हो सका है।

जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उभरा था। उसके पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठियों को बड़ा खतरा बताया गया था। चूंकि असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। पिछले दिनों बंगाल गए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बन जाए तो घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाला जाएगा। इसके पहले उन्होंने असम में कहा था कि यदि इस राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाए तो घुसपैठियों को निकालने में देर नहीं होगी। इसका अर्थ है कि असम में पिछले लगभग दस वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का काम नहीं किया जा सका। हर किसी को पूछना चाहिए आखिर क्यों? यह ठीक नहीं कि केवल चुनाव के समय घुसपैठियों की चर्चा की जाए और फिर कुछ न किया जाए। इससे तो घुसपैठिए और उन्हें घुसाने वाले सतर्क ही होते होंगे।

बांग्लादेशी घुसपैठियों से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में असम है। बांग्लादेशी असम के अलावा मेघालय और त्रिपुरा के रास्ते से भी घुससैठ करते हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला घुसपैठिया मेघालय के रास्ते ही मुंबई आया था। बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमावर्ती राज्यों में घुसकर इसलिए दूसरे राज्यों में जाने में सफल रहते हैं, क्योंकि वे कोई न कोई फर्जी पहचान पत्र हासिल कर लेते हैं। इसके बाद उनका काम आसान हो जाता है। पूर्वोत्तर और बंगाल में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली तक में बस गए हैं। यदा-कदा कुछ राज्य सरकारें उनकी पहचान करने का अभियान चलाती हैं, लेकिन अभी तक कोई अभियान प्रभावी नहीं सिद्ध हो सका है।

आपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात में हजारों बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। यह स्वाभाविक ही है कि इस अभियान के समय तमाम बांग्लादेशी अन्य राज्यों में खिसक गए होंगे। जो कहानी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, वही रोहिंग्याओं की भी है। रोहिंग्या भी पूर्वोत्तर और बंगाल के रास्ते घुसपैठ करने के बाद जिस तरह दिल्ली, हैदराबाद

और जम्मू तक में अपने ठिकाने बनाने में सफल हैं, उससे यह साफ है कि उन्हें भारत में लाने और बसाने का काम सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इस काम में लिप्त लोग घुसपैठियों को फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। ऐसा काम करने वाले बंगाल में खूब सक्रिय हैं।

निःसंदेह घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी सही है कि यदि राज्य सरकारें इस काम में केंद्र का सहयोग नहीं करतीं तो घुसपैठियों की पहचान आसान नहीं। बंगाल सरकार का यह कहना तो ठीक है कि यदि घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन केंद्र के इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि राज्य प्रशासन की ओर से घुसपैठियों को लेकर कभी कोई शिकायत क्यों नही की जाती? तथ्य यह है कि बंगाल के किसी भी थाने से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलती कि बांग्लादेश से किसी ने अवैध तरीके से प्रवेश किया है।

शिकायत इसलिए भी नहीं मिलती, क्योंकि स्थानीय नेता घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। एक समय ममता बनर्जी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाती थीं, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे घुसपैठियों को चिह्नित करने की किसी भी पहल का विरोध करती हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर के विरोध की एक बड़ी वजह यही आशंका है कि कहीं इससे घुसपैठियों की पहचान न हो जाए। बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होते ही सैकड़ों बांग्लादेशी अपने देश लौटने लगे थे।

कुछ समय बाद उनके लौटने का सिलसिला थम गया। कोई भी समझ सकता है कि यह इसीलिए थमा, क्योंकि उन्हें यह भरोसा हो गया होगा कि इस कवायद से उनकी पहचान नहीं होने वाली। हैरानी नहीं कि उनके संरक्षक नेताओं ने ही उन्हें यह भरोसा दिलाया हो कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो भी हो, इससे इन्कार नहीं कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। असम और बंगाल में तो उनकी इतनी संख्या हो गई है कि उन्होंने न केवल आबादी के संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया है, बल्कि वे कई क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति मंम आ गए हैं, क्योंकि वे छल-कपट से मतदाता बन गए हैं।

घुसपैठिए केवल देश के संसाधनों पर बोझ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी हैं। अब यह खतरा और अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे और इसका भरोसा नहीं कि वहां की नई सरकार की भारत से संबंध सुधारने में दिलचस्पी होगी। इन दिनों पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना हितैषी दिखाने के लिए न केवल हरसंभव जतन कर रहा है, बल्कि उसे भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। इन स्थितियों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया ही जाना चाहिए। जब नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था, तब यह कहा गया था कि उसे लागू करने के बाद राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात एनआरसी का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे किसी अभियान की कोई चर्चा नहीं। हर किसी को पूछना चाहिए आखिर क्यों?

राहुल गांधी के बोलने का कितना असर?

संसद के बाहर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के आपसी रिश्ते कैसे भी हों, संसद के भीतर और यहां तक कि संसद परिसर में भी उनके बीच एक तरह का बैर भाव दिखता है। इसका एक उदाहरण राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच के उस संवाद से मिला, जिसमें राहुल गांधी ने जब बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा तो जवाब में उन्हें उनसे देश का दुश्मन सुनना पड़ा। इसके पहले राहुल गांधी की उपस्थिति में ही पक्ष-विपक्ष के सांसदों के बीच धक्कामुक्की भी हो चुकी है, जिसमें सत्तापक्ष के एक सांसद प्रताप सिंह सारंगी को चोट भी लगी थी। इस मामले में एफआइआर भी दर्ज हुई थी। पता नहीं उसका क्या हुआ। संसद के भीतर तो पक्ष-विपक्ष के बीच न जाने कितनी बार झड़प हो चुकी है। विपक्षी सांसदों को कई बार उनके उग्र और अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित भी किया जा चुका है। पिछले दिनों भी लोकसभा से आठ सांसदों को निलंबित किया गया। जब ऐसा होता है तो संसद का चलना और कठिन हो जाता है।

यह बहुत आम है कि संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में कई दिनों तक केवल हंगामा होता रहता है। इस सत्र में लोकसभा में कई दिन तक इसलिए हंगामा होता रहा, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय चीन के अतिक्रमणकारी रवैये को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे। उन्हें इस आधार पर इसकी अनुमति नहीं मिली, क्योंकि यह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी का तर्क था कि वे एक पत्रिका में पुस्तक के अंश का उल्लेख करना चाह रहे हैं। उन्हें इसकी भी अनुमति नहीं मिली। इस पर हंगामा शुरू हो गया, जो कई दिनों तक जारी रहा। हालांकि राहुल गांधी इस पुस्तक के एक पत्रिका में प्रकाशित अंश को प्रमाणित करने का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत नहीं दी गई। इस पर जो हंगामा शुरू हुआ, वह कई दिनों तक जारी रहा।

जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इस पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है, पर उसके कुछ अंश सार्वजनिक हो चुके हैं। राहुल गांधी इन्हीं अंशों का लोकसभा में उल्लेख कर यह कहना चाहते थे कि जब चीनी सेना आक्रामक रवैया अपनाए थी, तब प्रधानमंत्री ने साहस का परिचय नहीं दिया और उन्होंने सेना को समुचित निर्देश भी नहीं दिए। कोई भी समझ सकता है कि वे यही साबित करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चीन की आक्रामकता से डर गए। राहुल गलवन की घटना के बाद से ही यह साबित करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से हिचक गए। उनका यह रवैया नया नहीं है। जब डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने थे, तब उन्होंने विवाद समझने के लिए भारतीय विदेश या रक्षा मंत्रालय से संपर्क साधने के बजाय चीनी राजदूत से मिलना आवश्यक समझा था। वे विदेश मंत्रालय को सूचित किए बिना गुपचुप रूप से उनसे मिलने पहुंच गए थे।

राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने के लिए यह भी दावा करते रहे हैं कि उनके पीएम रहते चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। वे एक बार यहां तक कह गए थे कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वे राफेल विमान सौदे पर प्रधानमंत्री को भ्रष्ट साबित करने के लिए यह कह भी चुके हैं कि उन्होंने अपने मित्रों को दलाली खाने का अवसर दिया। इस पर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी थी, लेकिन उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के मामले में उनका दावा है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर ऐसे काम कर रहा है कि भाजपा को चुनावी लाभ मिले। उन्होंने लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को खूब खरी-खोटी सुनाई थी और एक तरह से उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके इस दावे का दम निकाल दिया कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है, लेकिन वे वोट चोरी के अपने दावे पर अडिग हैं और यह साबित करने पर भी तुले हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा में मिलीभगत है।

राहुल गांधी अब यह साबित करना चाहते हैं कि किसी मजबूरी में आकर प्रधानमंत्री ने भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यापार समझौते पर सहमति दी और इस तरह अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। आपरेशन सिंदूर के समय भी राहुल गांधी का यही दावा था कि मोदी ने अमेरिकी दबाव के समक्ष घुटने टेक दिए। समस्या यह है कि भाजपा को यह लगता है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलने से वे सचमुच कमजोर या भारतीय हितों से समझौता करने वाले या फिर अक्षम शासक दिखने लगते हैं। यदि ऐसा होता तो आज शायद भाजपा विपक्ष में और कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सत्ता में होती। जब यह साफ है कि राहुल गांधी के कहने का कोई खास असर नहीं होता तो फिर वे संसद में या संसद के बाहर कुछ भी कहें, भाजपा को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे उन्हें और अधिक बोलने का मौका देना चाहिए।

बाबरी मस्जिद विवाद बन सकता है टीएमसी और भाजपा दोनों की संजीवनी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। हुमाऊं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी तो अब हिंदू संगठन ने बंगाल कूच करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रही है.इससे किसको होगा लाभ ?

पश्चिम बंगाल में 2 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घटना से राज्य की राजनीतिक फिजा में गर्माहट आने लगी है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से एक मस्जिद की नींव रखी गई। इसकी नींव टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमाऊ कबीर ने रखा है, लेकिन अब इसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं बनने देने का ऐलान किया है। लखनऊ की सड़कों पर 'मुर्शिदाबाद चलो' की अपील वाले तमाम पोस्टर लगाए गए हैं।हिंदू संगठनों ने लोगों से मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील की है। हिंदू संगठनों ने लिखा है, 'हुमायूं हम आएंगे', 'बाबरी फिर से गिराएंगे', 'बंटोगे तो कटोगे','चलो मुर्शिदाबाद'. अब हिंदू संगठन के लोग बंगाल के लिए कूच कर रहे हैं।

हुमायूं कबीर की अपनी राजनीति

जाहिर है एक तरफ हिंदू संगठन मुर्शिदाबाद चलकर बाबरी का विरोध की बात कर रहे हैं तो दुसरी तरफ हुमाऊं कबीर भी खुली धमकी दे रहे हैं. इस मुद्दे पर सियासी टकराव वाली स्थिति बन गई है.बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सवाल खड़े कर दिए हैं और सत्ताधारी पार्टी के भीतर की बेचैनी को उजागर कर दिया है. ऐसे में अब टीएमसी को सियासी तौर पर बेचैन कर दिया है। दरअसल

बाबरी मस्जिद के बहाने हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चला तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का पूरा प्लान बना रखा. इस तरह से उनकी नजर बंगाल के 30 फीसदी मुस्लिम वोटों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोटबैंक बना हुआ है. ऐसे में हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं।हिंदू-मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी कर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की ख्वाहिश सजा रहे हैं उसी का साइड इफेक्ट लखनऊ में लगे ये पोस्टर हैं. हिंदू संगठन के इस अपील पर हिंदुओं का जत्था मुर्शिदाबाद पहुंचता है तो ममता के लिए हिंदू और मुस्लिम वोटों के बीच

सियासी बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।हिंदू संगठन एक तरफ मुर्शिदाबाद चलकर बाबरी को किसी भी सूरत में नहीं बनने देने का ऐलान कर रहे हैं तो हुमाऊं कबीर ने भी खुली धमकी दे रहे हैं. इस मुद्दे पर सियासी टकराव वाली स्थिति बन गई है।

हिंदु संगठनो के अपील से राज्य में राजनीति गर्माई

पश्चिम बंगाल में हिन्दू मुस्लिम राजनीति का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना हुआ है। यहां टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हैं । इधर विश्व हिंदू रक्षा परिषद यूपी में बाबरी मस्जिद के विरोध में पोस्टर लगा रही है। तस्वीरों में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी तस्वीर लगाई है. इस तरह हिंदू संगठन नई बाबरी के निर्माण में सीधे-सीधे ममता बनर्जी को भी बराबर का शरीक मान रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद ही खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ बंगाल में इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है हुमायूं कबीर टीएमसी के ही आदमी है लिहाजा ममता बनर्जी के कहने पर राज्य के सियासत को गर्म रहे है।

पश्चिम बंगाल के100 सीटो पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है

दरअसल बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे के 294 सीटों में से करीब-करीब 100 पर निर्णयक भूमिका में हैं। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोटबैंक माना जाता है. ममता बनर्जी की लगातार तीन बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर ममता की चुप्पी इस बड़ी रणनीति का हिस्सा है , ताकि चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का बिखराव न हो । दूसरी तरफ

पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन किया था. 2014 में कांग्रेस और 2019 में वाम दलों के गिरते प्रदर्शन के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 42 में से 18 सीटें जीतीं. यह रुझान 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था. बंगाल में बीजेपी की सीटें भले ही 2019 की तुलना में 2024 में कम आईं हों, लेकिन हिंदू वोटों पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही है। ऐसे में बाबरी मस्जिद पर राजनीति दोनो ही दलो को सूट करतीं है।

एपस्टिन फाइल्स

शर्म, सन्नाटा और हमारी सामूहिक विफलता

यह भी एक सच है कि जनता को थकाने की बाकायदा रणनीति अपनाई जाती है। सूचनाओं की बाढ़, विरोधाभासी दावे, फर्जी खबरें और आधे-अधूरे सच–इन सबके जरिये भ्रम पैदा किया जाता है। और भ्रम से निष्क्रियता जन्म लेती है। निष्क्रिय समाज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है।

● डेस्क

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। जिन कांडों का खुलासा हो रहा है–जिनके वीडियो, दस्तावेज और गवाह सार्वजनिक हो चुके हैं–वे महज अपराध नहीं हैं, बल्कि मानवता के विरुद्ध सुनियोजित, संरक्षित और सत्ता-समर्थित हमले हैं। इन घटनाओं की भयावहता इतनी गहरी है कि शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर भी समाज इन्हें ह्लकंटेंटह्व की तरह उपभोग कर रहा है–चाव, रोमांच और क्षणिक घृणा के साथ–और फिर अगली सनसनी की ओर बढ़ जाता है।

यह कोई नई कहानी नहीं है। हर बड़े घोटाले, हर सामूहिक अपराध के बाद यही क्रम दोहराया गया है–पहले इनकार, फिर आंशिक स्वीकारोक्ति, उसके बाद माफी या इस्तीफा, और अंततः ह्लकम्पैरिटिवली बेहतरह्व का आत्मसंतोष। मानो न्याय कोई तुलनात्मक पैमाना हो, जहाँ कम बुरा होना ही अच्छा होने का प्रमाण बन जाए। पर असली सवाल कहीं गहरा है–जब अपराध हो रहे थे, तब आत्मा कहाँ थी? क्या नैतिकता केवल कैमरों के सामने ही जागती है?

इन कांडों की सबसे भयावह परत सत्ता से जुड़ी है। उच्चतम पदों पर बैठे लोग–जिन्हें समाज ईश्वरतुल्य मानता है–जब दोषियों से संवाद करते, उन्हें संरक्षण देते, उनसे लाभ लेते या उनके लिए रास्ते बनाते पाए जाते हैं, तब लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाती है। यह व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं, बल्कि संस्थागत अपराध है। क्योंकि जब अपराध को व्यवस्था का संरक्षण मिलता है, तब वह अपवाद नहीं रहता–वह एक प्रणाली बन जाता है।

मीडिया की भूमिका यहाँ निर्णायक होनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर वह भी दो ध्रुवों में बँटी नजर आती है–एक ओर सनसनी, दूसरी ओर चुप्पी। सनसनी पीड़ितों की गरिमा को रौंदती है, जबकि चुप्पी अपराधियों को समय और सुरक्षा देती है। टीआरपी, क्लिक और ट्रेंड की दौड़ में सत्य दम तोड़ देता है। नतीजा यह कि जनता को तथ्य नहीं, भावनात्मक

झटके मिलते हैं—और झटकों से स्थायी सामाजिक कार्रवाई कभी जन्म नहीं लेती।

कानून और जाँच एजेंसियों की स्थिति भी कोई आश्वस्ति नहीं देती। धीमी जाँच, अधिकार-क्षेत्र की उलझनें, राजनीतिक दबाव और अंतहीन प्रक्रियाएँ—ये सब मिलकर न्याय को टालने की एक सुव्यवस्थित मशीन बना देते हैं। कहा जाता है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान होती है; यहाँ यह कहावत एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आती है। पीड़ित थक जाते हैं, गवाह डर जाते हैं और अपराधी समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।

सबसे असहज प्रश्न फिर भी आम जनता से जुड़ा है। क्या सचमुच हमें लकवा मार गया है? या हमें इस तरह ढाला गया है कि हम क्रोधित तो हों, पर संगठित न हो सकें? सोशल मीडिया हमें आवाज देता है, लेकिन दिशा नहीं। हम पोस्ट करते हैं, साझा करते हैं, गालियाँ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। वास्तविक दुनिया में उतरने का धैर्य, जोखिम और निरंतरता—ये सब दुर्लभ होते चले गए हैं।

यह भी एक सच है कि जनता को थकाने की बाकायदा रणनीति अपनाई जाती है। सूचनाओं की बाढ़, विरोधाभासी दावे, फर्जी खबरें और आधे-अधूरे सच—इन सबके जरिये भ्रम पैदा किया जाता है। और भ्रम से निष्क्रियता जन्म लेती है। निष्क्रिय समाज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है।

कुछ देशों में माफि याँ माँगी जा रही हैं, कहीं इस्तीफे दिए जा रहे हैं और इन्हें बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन माफी तभी मायने रखती है जब उसके साथ जवाबदेही हो—कानूनी कार्रवाई, संपत्ति की जब्ती, नेटवर्क का खुलासा और स्थायी संस्थागत सुधार। केवल चेहरे बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इस्तीफा न्याय नहीं है; वह अधिकतम उसकी शुरूआत हो सकता है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष पीड़ितों का है। उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और उनका पुनर्वास—सब कुछ हाशिये पर धकेल दिया जाता है। जबकि न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं है; न्याय का अर्थ है पीड़ित की ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करना। काउंसलिंग, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और गवाह सुरक्षा—ये सब उतने ही आवश्यक हैं जितनी अदालत की कार्यवाही। इनके बिना न्याय हमेशा अधूरा रहेगा।

तो रास्ता क्या है? प्रतिशोध नहीं। हिंसा की कामना हमें उन दरिंदों से अलग नहीं बनाती जिनसे हम घृणा करते हैं। सभ्यता की जीत क्रूरता से नहीं, बल्कि जवाबदेही से होती है। इसके लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं पर समाज को एकजुट होना होगा।

पहला, स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय जाँच, क्योंकि सीमा-पार और सत्ता-समर्थित अपराधों में केवल राष्ट्रीय एजेंसियाँ पर्याप्त नहीं होतीं। दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरण—नाम, पद, नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन का सार्वजनिक खुलासा। तीसरा, कानूनी सुधार—विशेष अदालतें, समयबद्ध सुनवाई और मजबूत गवाह सुरक्षा कानून। चौथा, जिम्मेदार मीडिया, जो पीड़ित-केंद्रित, तथ्यपरक और निरंतर रिपोर्टिंग करे। पाँचवाँ, नागरिक एकजुटता—शांतिपूर्ण, संगठित और लगातार दबाव। क्योंकि बदलाव किसी एक पोस्ट से नहीं, बल्कि निरंतरता से आता है।

अंततः यह लड़ाई नैतिकता की है। हर समाज को कभी न कभी यह तय करना पड़ता है कि वह सुविधा चुनेगा या सत्य। सुविधा हमें सुला देती है, जबकि सत्य हमें बेचैन करता है—और इतिहास हमेशा उसी बेचैनी से आगे बढ़ता है। लानत दरिंदों पर तो बनती है। लेकिन इतिहास हमें इस आधार पर परखेगा कि क्या हमने अपने आक्रोश को क्षणिक नफरत में गँवा दिया, या उसे परिवर्तन की संगठित ताकत में बदला। चुप्पी अब विकल्प नहीं है। देर से सही, पर न्याय आना चाहिए—और ऐसा न्याय, जो केवल दोषियों को दंडित न करे, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाए। यही इस समय की सबसे बड़ी माँग है और यही हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी।

बंगाल चुनाव में भाजपा का बड़ा दांव

भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक है और वह घुसपैठ के मुद्दे को लगातार पूरे जोर शोर से उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। राज्य में भाजपा इसे घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करार दे रही है। इससे राज्य का पूरा चुनावी माहौल अवैध घुसपैठ और बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या के आसपास सिमटता दिख रहा है।

अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगल में विधानसभा का चुनाव होना है । ऐसे में बीजेपी ने चुनाव जितने के लिए कई स्तर पर प्लान बनाई है । इस लिहाज से भाजपा

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को बड़ा मुद्दा बना सकतीं है। जिसके चलते चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी एसआई को लेकर हमलावर है तो दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक है और वह घुसपैठ के मुद्दे को लगातार पूरे जोर शोर से उठा रही है।

बंगाल में अवैध घुसपैठ है ज्यादा फोकस

बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्या पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्याओं से पश्चिम बंगाल के हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ रहा है। इस माहौल में पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है। भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक है और वह घुसपैठ के मुद्दे को लगातार पूरे जोर शोर से उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। राज्य में भाजपा इसे घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करार दे रही है। इससे राज्य का पूरा चुनावी माहौल अवैध घुसपैठ और बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या के आसपास सिमटता दिख रहा है। ममता बनर्जी को इसका नुकसान हो सकता है।

सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा असर

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की काफी आबादी अधिक है और अकेले मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन यही वे इलाके हैं जहां अवैध घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों ने लंबे समय से यहां रहते

हुए भारतीय पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए हैं। लेकिन अब इनमें से कई जांच एजेंसियों की पकड़ में आ रहे हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है।

भाजपा के प्रमुख मुद्दे

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी पश्चिम बंगाल में स्थानीय मुद्दों के सहारे अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा की कई टीमें लगातार पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में काम कर रही हैं। इन इलाकों में काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ता उन मुद्दों की पहचान कर रहे हैं जिसके सहारे भाजपा ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा सकती है। इन्हीं मुद्दों पर आक्रामक चुनाव प्रचार कर भाजपा जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी।

हालांकि, पूरे राज्य के स्तर पर भाजपा अवैध घुसपैठियों के द्वारा आम बंगाली मानुष की रोजी-रोटी छीने जाने का मुद्दा लगातार उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ भाजपा के हर नेता इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। इसके अलावा तृणमूल कार्यकताओं द्वारा किया जा रहा कथित भ्रष्टाचार भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा है।

बदलाव को हवा देने की हो रही है कोशिश

पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल में ळटउ की सरकार है। ऐसे में भाजपा का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है। उसने एक बदलाव की उम्मीद से ही वामदलों को छोड़कर ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। लेकिन जनता ने पाया कि उसने एक अराजक को छोड़ दूसरे अराजक को चुन लिया है। लेकिन अब भाजपा इन क्षेत्रों में लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी है। लोग बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बननी तय है।

जिस तरह ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बाधा पैदा की है, उससे एक केंद्रीय जांच एजेंसी और किसी राज्य सरकार के बीच सीधे टकराव का मामला बनता दिखाई दे रहा है। क्या यह लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? अमर उजाला के इस प्रश्न पर भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कभी भी देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय तक को नहीं छोड़ा। अब सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग पर अंगुली उठाई जा रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इसके सहारे वे केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए अब समय निकल चुका है। जनता ने विपक्ष का भ्रष्टाचार देख लिया है और अब वह उन्हें बदलकर व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी। भाजपा विकास, अवैध घुसपैठ के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस कार्यकताओं द्वारा राज्य में किये जा रहे भ्रष्टाचार सहित बदलाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता स्वयं बदलाव के मूड में है। वह देख रही है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के दूसरे हिस्सों का विकास हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी आज जनता और विकास के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस दीवार को गिराना चाहती है।

ममता बना रही है एसआईआर को बड़ा मुद्दा

एसआईआर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध भी इन्हीं जिलों में देखा जा रहा है। कहा जाता है कि ये मतदाता ममता बनर्जी के ठोस समर्थक हैं। पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी ने इन इलाकों में क्लीन स्वीप किया था। तमाम विरोधों के बाद भी इन इलाकों में टीएमसी की दावेदारी आज भी बहुत मजबूत है। एसआईआर से कटने वाले हर वोटर को यहां ममता बनर्जी के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह यूपी-बिहार में भारी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, यहां भी भारी संख्या में वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटना तय माना जा रहा है। इसका चुनाव पर कुछ असर पड़ना तय है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या ही यहां निर्णायक रहने वाली है। ममता बनर्जी की एसआईआर से नाराजगी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है।

मासिक धर्म और सैनिटरी पैड

स्कूलों में गरिमा की परीक्षा

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं का अभाव महिलाओं और किशोरियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जब किसी छात्रा को असुरक्षित और अवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को मजबूर होना पड़े, तो यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा आघात है।

● डॉ प्रियंका सौरभ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और मासिक धर्म स्वच्छता को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय समाज की उस सामूहिक सोच को आईना दिखाते हैं, जिसमें आज भी मासिक धर्म को संकोच, चुप्पी और उपेक्षा के साथ देखा जाता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म महज स्वास्थ्य या स्वच्छता का मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है।

भारत जैसे देश में, जहाँ संविधान समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है, वहाँ लाखों छात्राओं का मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर होना व्यवस्था की गहरी विफलता को उजागर करता है। अदालत का यह हस्तक्षेप इसी विफलता को दूर करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह याद दिलाता है कि अधिकार केवल कागजों में दर्ज घोषणाएँ नहीं होते, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ तभी है, जब वे जमीनी हकीकत में दिखाई दें।

मासिक धर्म को लंबे समय तक केवल एक जैविक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय या स्कूल प्रबंधन की सीमित जिम्मेदारी बनकर रह गया। सच्चाई यह है कि मासिक धर्म सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक स्तर पर गहरे प्रभाव डालता है। स्वच्छता सुविधाओं और सही जानकारी के अभाव में छात्राओं को न केवल संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है, बल्कि शर्म और भय के कारण वे नियमित रूप से स्कूल आने से भी कतराने लगती हैं। कई मामलों में यह स्थिति स्थायी स्कूल ड्रॉपआउट का कारण बन जाती है।

अनेक अध्ययन यह दशार्ते हैं कि मासिक धर्म के दौरान उचित प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में किशोरियाँ हर महीने कई दिनों तक स्कूल नहीं जातीं। यह अनुपस्थिति धीरे-धीरे सीखने की प्रक्रिया को कमजोर करती है और अंततः शिक्षा से पूरी तरह कट जाने का जोखिम बढ़ा देती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में हरसबके लिए शिक्षाह्व के लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, या यह केवल नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित नारा

बनकर रह गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जब स्कूलों में अलग और स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, साबुन और सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो छात्राओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय जाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि जहाँ लड़कों की शिक्षा बिना किसी जैविक बाधा के चलती रहती है, वहीं लड़कियों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पीछे धकेल दिया जाता है।

यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के विरुद्ध है, जो समानता और भेदभाव-रहित समाज की अवधारणा को आधार प्रदान करते हैं। केवल अवसर की समानता पर्याप्त नहीं होती, जब तक उस अवसर तक पहुँचने के साधन भी समान न हों। मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी करके हम अनजाने में ही लड़कियों को उस बराबरी से वंचित कर देते हैं, जिसका वादा संविधान करता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं का अभाव महिलाओं और किशोरियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जब किसी छात्रा को असुरक्षित और अवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को मजबूर होना पड़े, तो यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा आघात है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं करता, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस धारणा को तोड़ता है कि सैनिटरी पैड या स्वच्छ शौचालय कोई ह्लअतिरिक्त सुविधाह्व हैं। वास्तव में ये आवश्यक अधिकार हैं, जिनके बिना न तो स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है और न ही शिक्षा का अधिकार सार्थक हो सकता है। इस दृष्टि से अदालत का यह आदेश एक सामाजिक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

हालाँकि भारत में न्यायिक आदेशों की सबसे बड़ी चुनौती उनके प्रभावी क्रियान्वयन में दिखाई देती है। कई बार नीतियाँ और दिशा-निर्देश घोषणाओं और फाइलों तक सीमित रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यह निर्णय केवल अदालती आदेश या कानूनी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक असर स्कूलों और छात्राओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए। सरकारी और निजी, शहरी और ग्रामीण–सभी स्कूलों में इन निदेशों को समान रूप से लागू करना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में निजी स्कूलों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर निजी शिक्षण संस्थान स्वयं को सरकारी योजनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग मान लेते हैं। अदालत का आदेश इस सोच को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और बताता है कि बच्चों के अधिकार के मामले में सरकारी और निजी का भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि निजी स्कूल उच्च शुल्क वसूल सकते हैं, तो वे छात्राओं की बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि केवल आदेश और नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक ऐसी पहल अधूरी ही रहेंगी। मासिक धर्म को लेकर फैली चुप्पी, अंधविश्वास और शर्म की भावना इस समस्या को और जटिल बनाती है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केवल पैड वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता, संवाद और वैज्ञानिक जानकारी को भी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। लड़कों को भी इस चर्चा से अलग नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील और समान समाज की नींव तभी पड़ती है, जब समझ साझा होती है।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह आदेश केवल अनुपालन की बाध्यता नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। पर्याप्त बजट आवंटन, प्रभावी निगरानी तंत्र और स्पष्ट जवाबदेही तय किए बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती। अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा यह स्पष्ट संकेत देती है कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता।

अंततः यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसके सबसे कमजोर वर्ग के साथ किए गए व्यवहार से होता है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक सुविधाएँ देना कोई उपकार नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अब असली परीक्षा यह है कि यह निर्णय कागजों से निकलकर जमीन पर उतरता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल स्कूलों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि उस सोच को भी बदलने की दिशा में निर्णायक कदम होगा, जो अब तक मासिक धर्म को अधिकार नहीं, बल्कि बोझ समझती आई है।

क्या हिंदुओं की जातीय मानसिकता को बदल पाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत?

● कमलेश पांडेय

प्राचीनकाल में मनुस्मृति से लेकर आधुनिक काल के संविधान तक हिंदू समुदाय में जिस जातिवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा दिया गया, वह अब दुनिया के तीसरे बड़े धर्म सनातन (हिन्दू) के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जिस तरह से सियासी गोलबंदी के लिए जातिवाद को हवा दी जा रही है, वह किसी लोकतांत्रिक कलंक से कम नहीं है। अब तो प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय भी इसे हवा देते प्रतीत हो रहे हैं।

मसलन, इससे निरंतर कमजोर हो रहे हिन्दू समाज की एकजुटता के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की चिंता स्वाभाविक है। यह उन जैसे सैकड़ों मशहूर लोगों के लिए भी सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है लेकिन हमारी संसद और सरकार के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि जातिवादी खिलौने से मतदाताओं को फुसलाने की संवैधानिक तरकीब उसने विकसित कर ली है और आधिकारिक निर्णयों में भी इसका भौंडा प्रदर्शन दिखाई दे जाता है।

> फिलवक्त मोहन भागवत ने बताया कि जाति मूल रूप से पेशे से जुड़ी थी लेकिन बाद में भेदभाव का कारण बनी। उन्होंने जोर दिया कि कानून या घोषणाओं से नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने से यह जटिल समस्या हल होगी।

बता दें कि विगत 18 जनवरी 2026 को छत्रपति संभाजीनगर में संघ सरचालक मोहन भागवत ने कहा कि जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए जाति को मन से मिटाना होगा जो ईमानदारी से करने पर 10-12 वर्षों में संभव है। एक तरह से उनका यह बयान जातिवाद की गहरी जड़ों को देखते हुए आशावादी तो लगता है लेकिन इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठते हैं क्योंकि जाति भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में गहराई से बसी हुई है।

अब तो संविधान से लेकर जनगणना तक इसने घुसपैठ कर ली है। इसलिए जब तक सत्ता प्रतिष्ठान को सद्बुद्धि नहीं आएगी, तबतक जाति मुक्त भारत या हिन्दू समाज की परिकल्पना बेमानी प्रतीत होती है। इसलिए यक्ष प्रश्न पुनः समुपस्थित है कि क्या हिंदुओं की जातीय मानसिकता को बदल पाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत? क्या जाति आधारित आरक्षण सम्बन्धी सोच को बदल पाएंगे मोहन भागवत क्योंकि जबतक ऐसा नहीं होगा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाफी प्रतीत होंगी!

फिलवक्त मोहन भागवत ने बताया कि जाति मूल रूप से पेशे से जुड़ी थी लेकिन बाद में भेदभाव का कारण बनी। उन्होंने जोर दिया कि कानून या घोषणाओं से नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने से यह जटिल समस्या हल होगी। देखा जाए तो यह युगांतरकारी विचार पहले भी व्यक्त किया गया है जैसे 2023 में जाति को 'पंडितों की देन' उन्होंने ही बताया था लेकिन नेताओं और नौकरशाहों की संवैधानिक हठधर्मिता शायद उन्होंने विस्मृत कर डाली ताकि आरक्षणवादी कोहराम न मचाएं।

कहना न होगा कि जातिवाद मुक्त भारत और हिन्दू समाज की राह में कई व्यवहारिक चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि जातिवाद ग्रामीण रोजगार, विवाह और राजनीति में प्रबल है जहां आरक्षण और वोट बैंक इसे बनाए रखते हैं। भले ही प्रतिक्रियाओं में इसे 'चुनावी जुमला' कहा गया, क्योंकि ऐसे बयान कार्रवाई में नहीं बदलते। यही वजह है कि सामाजिक सुधारों के बावजूद अंतरजातीय विवाह कम हैं और भेदभाव जारी है।

यह ठीक है कि इस दिशा में जारी ईमानदार प्रयास से जागरूकता बढ़ सकती है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और कानूनी सख्ती के बिना 10-12 वर्षों का लक्ष्य अवास्तविक लगता है। फिर

भी यदि यह पुनीत सपना साकार होता है तो इससे नागरिक समाज, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिल सकती है। वहीं नागरिक समाज, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से ही यह पवित्र सपना साकार होगा।

देखा जाए तो आरएसएस ने जातिवाद समाप्ति के लिए लंबे समय से सामाजिक समरसता व सामाजिक सद्भाव को प्रमुख लक्ष्य बनाया है जिसमें जागरूकता अभियान, गांव-स्तरीय प्रयास और शाखाओं के माध्यम से कार्यकताओं को प्रेरित करना शामिल है हालांकि, आलोचक इसे सतही मानते हैं क्योंकि संगठन की आंतरिक संरचना और ऐतिहासिक रुख में जातिगत प्रभाव दिखता रहा है।

बावजूद इसके, आरएसएस ने 2023 से 'सामाजिक समरसता परियोजना' शुरू की जिसमें 13,000+ गांवों में कुओं, श्मशानों और मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक हटाने का सर्वे और जागरूकता अभियान चलाया। वहीं संघ शाखाओं (95,000+) के जरिए कार्यकर्ता गांवों, स्कूलों और मंदिरों में जाकर छुआछूत विरोधी संदेश फैलाते हैं, साथ में सामूहिक भोज के द्वारा भोजन करते हैं और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देते हैं।

यही वजह है कि बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे चुनावों में हिंदू वोटों को जाति से ऊपर उठाने में संघ की उपर्युक्त पहल सहायक साबित हुई जिससे भाजपा को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। साथ ही शाखाओं में जाति-निरपेक्षता का वातावरण स्थापित हुआ। यही नहीं, संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठकों में भी इसे प्राथमिकता दी गई जैसे 2024 के आम चुनावों तक इस विषयक अभियान चलाने का फैसला संपन्न हुआ।

वहीं, संगठन के भीतर जारी आंतरिक प्रयास के तहत संघ की शाखाओं में जाति को नजरअंदाज कर 'सभी हिंदू एक परिवार' का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसकी शुरूआत संस्थापक हेडगेवार ने की थी। वहीं, संवैधानिक आरक्षण पर भी समर्थन जताया गया है ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों आदि

का भरोसा आरएसएस में मजबूत हो हालांकि हालिया बयानों में इसे जातिवाद बढ़ाने वाला भी कहा गया। साथ ही साल 2024 में जाति जनगणना का संघ ने समर्थन किया ताकि योजनाएं बेहतर हों, बशर्ते राजनीतिक दुरुपयोग न हो।

कहना न होगा कि आरएसएस के इन सदाशयी प्रयासों के बावजूद, उस पर ब्राह्मण वर्चस्व और आरक्षण विरोध के पुराने आरोप लगते रहे हैं। आरएसएस के जातिवाद विरोधी प्रयासों पर कई गंभीर आलोचनाएं भी आई हैं जो मुख्य रूप से इनके प्रचारात्मक, असंगठित और हिंदू एकता को प्राथमिकता देने वाले स्वरूप पर केंद्रित हैं जिसके चलते आलोचक इन्हें सतही बताते हैं क्योंकि संगठन ने जाति व्यवस्था को जड़ से चुनौती नहीं दी।

अक्सर सवाल उठाया जाता है कि विगत 100 वर्षों में कोई प्रमुख दलित या आदिवासी संघ सरसंघचालक नहीं बना जिससे आंतरिक ब्राह्मण वर्चस्व के आरोप बने हुए हैं। आरक्षण पर अस्पष्ट रुख और जाति जनगणना को राजनीतिक दुरुपयोग रोकने की शर्त रखना आलोचना का कारण बना। वहीं छुआछूत जैसी प्रथाएं ग्रामीण भारत में बनी हुई हैं।

अलबत्ता, मोहन भागवत जैसे नेताओं के बयान सकारात्मक हैं लेकिन व्यावहारिक बदलाव सीमित दिखते हैं क्योंकि जाति राजनीति में गहरी पैठ रखती है। भले ही भागवत के समग्र मूल्यांकन प्रयासों से जनजागरूकता बढ़ी लेकिन जाति राजनीति और सामाजिक जड़ों को तोड़ने में ये पहल अपर्याप्त साबित हुए। ऐसा इसलिए कि गहरे बदलाव के लिए राजनीतिक समर्थन और कानूनी सख्ती की स्पष्ट कमी रही।

यही वजह है कि आरएसएस के जातिवाद विरोधी प्रयासों में सीमित सफलता मिली है जो मुख्यतः जागरूकता और कुछ स्थानीय स्तर के बदलावों तक सीमित रहकर, जबकि व्यापक सामाजिक परिवर्तन में असफलता दिखती है। आलोचकों के अनुसार, ये प्रयास हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए प्रतीत होते हैं न कि जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए।

जहां तक आरएसएस की ऐतिहासिक और वैचारिक कमियों की बात है तो संघ ने कभी जाति-विनाश का आंदोलन नहीं चलाया और वर्ण व्यवस्था पर अमूमन मौन रहा जो तार्किकता वश स्वाभाविक बात है। वहीं, आरक्षण विरोधी भागवत के पुराने बयानों से दलित-बहुजन असंतुष्ट हैं और उनके प्रयासों को छुआछूत रोकने तक सीमित माना जाता है। इतना ही नहीं, आरएसएस के समरसता सम्बन्धी अभियानों को सतही तक कहा जाता है क्योंकि ये जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने के बजाय छुआछूत जैसे सतही लक्षणों को ही लक्षित करते हैं, जबकि वर्णाश्रम धर्म को अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखते हैं।

यही वजह है कि आरएसएस के दलित-ओबीसी आलोचक इन्हें हिंदू एकता मजबूत करने का प्रचार माध्यम मानते हैं न कि सच्चे सामाजिक न्याय का उपकरण। खासकर वर्ण व्यवस्था पर मौन अभियान अस्पृश्यता विरोधी दिखते हैं लेकिन जन्म-आधारित जाति और वर्ण प्रथा को चुनौती नहीं देते जो भेदभाव की मूल जड़ है। यह ठीक है कि आरएसएस विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे नेताओं ने समरसता को हिंदू संगठन की पूर्वशर्त बनाया जबकि कांशीराम जैसे दलित नेताओं को उन्होंने 'बाधक' कहा।

उधर, आरएसएस के पूर्व सदस्यों ने भी शाखाओं में जातिगत भेदभाव का खुलासा किया है। पूर्व कारसेवक भंवर मेघवंशी जैसे लोगों ने भी शाखाओं में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। जिससे दशकों बाद भी कोई व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखा और 99 वर्षों में भी शीर्ष दलित नेता का अभाव सतहीपन दशार्ता है। लिहाजा, आरएसएस के सामाजिक समरसता अभियानों को विपक्षी ताकतों के खिलाफ हिंदू एकता मजबूत करने का हथियार माना जाता है न कि वास्तविक सामाजिक न्याय का।

पर भारतीय ट्रेड कूटनीति के मायने

● **कमलेश पांडेय**

दावोस में चली विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक में भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां पर भारतीय ट्रेड कूटनीति ने जो पॉलिसी नैरेटिव सेट किए और ग्लोबल इमेज विकसित किया, वह यहां कई मायने में अहम है। सबसे बड़ी बात तो यह कि यहां पर भारत ने वैश्विक निवेशकों के सामने खुद को चीन का वैकल्पिक हब के रूप में प्रस्तुत किया और विकसित भारत होने का स्थायी नजरिया पेश किया।

दरअसल, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने जिस आर्थिक स्थिरता, वैश्विक लोकतंत्र और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना पर बल दिया, उससे वैश्विक नीति-निर्धारण में इंडिया की भूमिका और अधिक मजबूत हुई। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की कीमत पर अमेरिका नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु एक से बढ़कर एक जोखिम भरे दांव चल रहा हो, उस दौर में भी भारत की यह अहम उपस्थिति बहुत कुछ चुगली करती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के मोदी सरकार के इरादे स्पष्ट हैं जिसे भरपूर दुनियावी समर्थन भी मिल रहा है। इसके अहम आर्थिक व कूटनीतिक मायने हैं।

देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख उद्योगपतियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल ने जिस तैयारी के साथ शिरकत की और निजी वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया, उसका रणनीतिक महत्व है। इस दौरान देखा गया कि दावोस में भारत का प्रतिनिधिमंडल रेल, आईटी, ऊर्जा और उद्योग जैसे मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक फैला हुआ था जबकि रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, इंफोसिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट दिग्गजों की भागीदारी ने निजी क्षेत्र में भारत की अहम ताकत दिखाई।

इससे नानाविध लाभ मिला और निवेश समझौते हुए, जैसे महाराष्ट्र के लिए हजारों करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर होना। इससे दावोस में भारत पर चर्चा का केंद्र बना रहा। चर्चा भी वह कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का नया हब बन सकता है, खासकर दिन ब दिन बदलते भू-राजनीतिक तनावों के बीच। सबसे खास बात यह कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अध्यक्ष ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए पीएम मोदी के सुधारों और ग्लोबल साउथ की आवाज की भरपूर सराहना की। इससे भारत-ईयू व्यापार समझौते पर भी सकारात्मक इनपुट के संकेत मिले।

इस तरह से देखा जाए तो दावोस (WEF 2026) की मौजूदा बैठक से भारत को सीधे-सीधे दो तरह के बड़े फायदे मिलते दिखाई दे रहे हैंझ पहला,

निवेश व व्यापार के ठोस मौके, और दूसरा, भारत की छवि व कूटनीतिक प्रभाव में बढ़त। वहीं, निवेश और जॉब के बेशुमार मौके मिलने की बात अलग है। कहना न होगा कि भारत का पवेलियन और अलग-अलग राज्य (खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि) दावोस में निवेश आकर्षित करने के लिए आक्रामक तरीके से रोडशो, मीटिंग और एमओयू साइन कर रहे हैं, जिनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग, हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर व डिजिटल इकोनॉमी पर है।

दरअसल पिछले सालों के ट्रेंड के आधार पर दावोस प्लेटफॉर्म से भारत को अरबों डॉलर के निवेश आश्वासन मिलते रहे हैं, जो बाद में प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप फंडिंग के रूप में नौकरियां और उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं।

वहीं इस बार की खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस में भारतीय बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट लीडर्स के साथ विशेष बैठक कर रहे हैं, जिसे संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यदि यहां किसी प्रकार की रूपरेखा या राजनीतिक सहमति बनती है तो आगे चलकर टैरिफ, मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजी/डिफेंस कोऑपरेशन में भारत के लिए बेहतर शर्तें निकल सकती हैं।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) पर भारत को 'सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था', ग्लोबल ग्रोथ में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देने की क्षमता वाला देश और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इससे भारत की पॉलिसी नैरेटिव मजबूत हुई है और देश के ग्लोबल इमेज में उत्तरोत्तर सुधार होते रहने के संकेत मिले हैं। ऐसा इसलिए कि अश्विनी वैष्णव जैसे नरेंद्र मोदी के कुशल मंत्री वहाँ अगले 5 साल के लिए 6-8% ग्रोथ, 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 5 गुना करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर रिफॉर्म और डिजिटल पब्लिक इंफ्रा (UPI आदि) जैसे एजेंडा को सफलता पूर्वक पेश कर रहे हैं, जिससे विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ता है।

उनकी कोशिशों से भारत के राज्यों को भी भरपूर लाभ मिलने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर व मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को ग्लोबल प्लेयर्स के सामने रख कर अलग से निवेश आकर्षित कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावनाएं बढ़ती हैं। वहां देखा गया कि दावोस का ह्लइंडिया पवेलियनह्व अब डील-मेकिंग का हब बन चुका है, जहाँ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से ह्लटीम इंडियाह्व के रूप में प्रेजेंट हो रही हैं। इससे दुनिया को स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत में नीतिगत स्थिरता और कोऑर्डिनेशन की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही दावोस से सीधे सीधे किसी को सब्सिडी या स्कीम नहीं मिलती है, लेकिन वहां तय हुए निवेश, व्यापार समझौते, और पॉलिसी भरोसे का असर मीडियम टर्म में नौकरियों, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में स्पष्ट दिखता है। यहां पर यदि भारत निवेश का भरोसेमंद सेंटर बनता प्रतीत होता है तो मैन्युफैक्चरिंग/ग्रीन एनर्जी/डिजिटल सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, जिसका असर वेतन, लोकल इकोनॉमी, टैक्स रेवेन्यू और कल्याणकारी व्यय पर पड़ेगा, जो अंततः आम नागरिक तक पहुँचेगा।

यही वजह है कि दावोस की हालिया विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026 बैठक में भारत ने निवेश आकर्षण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित प्रमुख पहलों की घोषणा की, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी योजनाएं शामिल रहीं। ये घोषणाएं महाराष्ट्र, असम और झारखंड जैसे राज्यों में ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रा पर फोकस करती हैं।

यदि उपलब्धियों की बात करें तो अडानी ग्रुप ने एविएशन, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में 6 लाख करोड़ रुपये (लगभग 6.6 बिलियन डॉलर) के निवेश का ऐलान किया। इसमें असम में 2700 मेगावाट सौर क्षमता, महाराष्ट्र में धारावी पुनर्विकास, नवी मुंबई एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स, 3000 मेगावाट ग्रीन डेटा सेंटर, 8700 मेगावाट पंप्ड स्टोरेज और सेमीकंडक्टर फैब शामिल हैं। यह 7-10 वर्षों का प्लान रोजगार सृजन और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देगा। वहीं, झारखंड में टाटा स्टील ने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता जताई जबकि महाराष्ट्र ने रायगढ़-पेण ग्रोथ सेंटर की घोषणा की, जो 1 लाख करोड़ के निवेश का केंद्र बनेगा।

देखा जाए तो दावोस में वैश्विक साझेदारियां मजबूत हुई हैं। यहीं पर भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर सकारात्मक प्रगति हुई, जिसे ईयू प्रमुख ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई (AI) समिट होस्ट करने की घोषणा की जो भारत के वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करेगी। वहीं ये पहलें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने पर जोर देती हैं। कुलमिलाकर दावोस बैठक से भारत को प्राप्त निवेश प्रतिबद्धताएँ निम्नलिखित हैं जो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी पर केंद्रित हैं, जो लाखों नौकरियाँ पैदा करने की क्षमता रखती हैं। इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 5-10 लाख नौकरियाँ बनने का अनुमान है, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े व अहम राज्यों में।

पिछले दावोस चक्रों के आधार पर 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश से औसतन 5-8 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ (फैक्ट्री वर्कर, इंजीनियर) और दोगुने अप्रत्यक्ष रोजगार (लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज) उत्पन्न होते हैं। हरित ऊर्जा व डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स से विशेष रूप से 2-3 लाख हाई-स्किल्ड जॉब्स (टेक्नीशियन, एनालिस्ट) बनेंगी। पहला, मैन्युफैक्चरिंगः फैक्ट्री ऑपरेटर, स्किल्ड वेल्डर, क्वालिटी कंट्रोलर- 3 लाख+ जॉब्स, मुख्यतः स्किल्ड/सेमी-स्किल्ड श्रमिक। दूसरा, हरित ऊर्जाः सोलर इंस्टॉलर, विंड टरबाइन टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर झ्र 1-2 लाख जॉब्स, फोकस इंजीनियरिंग व सस्टेनेबिलिटी स्किल्स पर। तीसरा, डेटा सेंटर/डिजिटलः सर्वर एडमिन, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टझ्र 1 लाख+ हाई-पे जॉब्स, आईटी/सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड वालों के लिए।

जहां तक इसके क्षेत्रीय प्रभाव की बात है तो उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर व डेटा सेंटर से स्थानीय स्तर पर 2 लाख+ जॉब्स, जिसमें 40% महिलाओं/युवाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से अतिरिक्त 1-2 लाख रोजगार जोड़ेंगे। इन जॉब्स में 60% स्किल्ड (ITI/डिप्लोमा) की जरूरत होगी, इसलिए ITI व अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ेगा। देरी से बचने के लिए एमओयू लागू करने पर सबकुछ निर्भर करेगा अन्यथा सिर्फ 50-70% ही मटेरियलाइज होंगी।

ग्रीनलैंड

आखिर अमेरिका को क्यों चाहिए

● राजेश जैन

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल लगभग 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर लेकिन आबादी सिर्फ 60 हजार के आसपास। यहां का 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। न घने जंगल, न हाईवे, न चमकते शहर। कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं और कई महीनों तक रात खत्म नहीं होती। देखने में शांत, ठंडा और वीरान लगने वाला यह द्वीप आज वैश्विक राजनीति के सबसे गर्म मोर्चों में बदल चुका है। वजह है- अमेरिका की पुरानी लेकिन अब खुली और आक्रामक चाहत। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है-ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में चाहिए लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इस बर्फीले, कम आबादी वाले द्वीप की इतनी जरूरत क्यों है और क्या अमरीका इसे हासिल कर पाएगा।

सामरिक महत्व

ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह स्थित है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच सेतु जैसा काम करता है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पास ही रूस, नीचे यूरोप और पश्चिम में अमेरिका। मतलब साफ है-जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, वह आर्कटिक का चौकीदार बन जाता है। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस- हर मोर्चे पर मुकाबला है। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से मौजूद है। यहां स्थित थुले एयर बेस (अब पिटुफिक स्पेस बेस) अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यहीं से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करता है। अगर अमेरिका को पूरा ग्रीनलैंड मिल जाता है तो वह आर्कटिक का फुल कंट्रोल सेंटर बन सकता है। रूस लगातार आर्कटिक में नए सैन्य ठिकाने, नई पनडुब्बियां, नए एयरबेस और नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रूस पर नजर रखने का वॉच टावर है।

सामरिक महत्व

ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह स्थित है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच सेतु जैसा काम करता है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पास ही रूस, नीचे यूरोप और पश्चिम में अमेरिका। मतलब साफ है-जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, वह आर्कटिक का चौकीदार बन जाता है। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस- हर मोर्चे पर मुकाबला है। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से मौजूद है। यहां स्थित थुले एयर बेस (अब पिटुफिक स्पेस बेस) अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यहीं से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करता है। अगर अमेरिका को पूरा ग्रीनलैंड मिल जाता है तो वह आर्कटिक का फुल कंट्रोल सेंटर बन सकता है। रूस लगातार आर्कटिक में नए सैन्य ठिकाने, नई पनडुब्बियां, नए एयरबेस और नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रूस पर नजर रखने का वॉच टावर है।

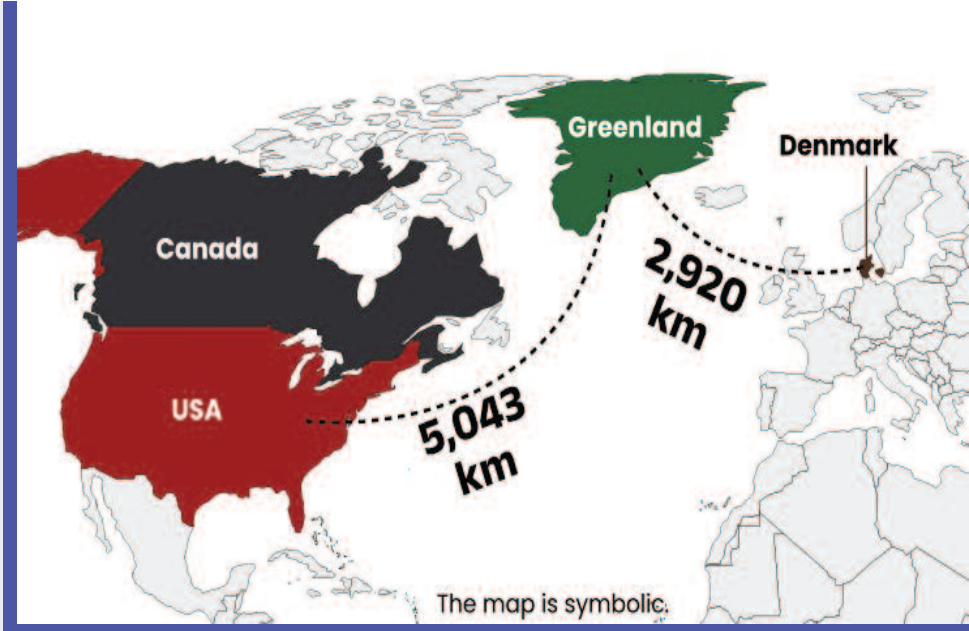

डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रुख

बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क का साफ संदेश है- ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार, अपनी संसद और अपनी पहचान है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे डरिक्सन ने अमेरिकी प्रस्ताव को बेतुका बताया। ग्रीनलैंड के नेताओं ने कहा-यह जमीन नहीं, हमारी आत्मा है। यूरोप के देशों ने भी डेनमार्क का समर्थन किया।

ग्रीनलैंड बिकेगा, इसकी संभावना लगभग शून्य है क्योंकि आज दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, कानून, संप्रभुता और जनमत से चलती है लेकिन दबाव जारी रहेगा- कभी आर्थिक, कभी कूटनीतिक, कभी रणनीतिक।

बहरहाल, अमेरिका, चीन और रूस; तीनों की नजरें इसी बर्फीली धरती पर टिकी हैं। बाहर से शांत दिखने वाला ग्रीनलैंड असल में भविष्य की वैश्विक राजनीति का रणक्षेत्र है। यह द्वीप तय करेगा कि आने वाले दशकों में कौन सुपरपावर रहेगा।

को कंट्रोल करता है, वह आर्कटिक का चौकीदार बन जाता है। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस- हर मोर्चे पर मुकाबला है। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से मौजूद है। यहां स्थित थुले एयर बेस (अब पिटुफिक स्पेस बेस) अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यहीं से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करता है। अगर अमेरिका को पूरा ग्रीनलैंड मिल जाता है तो वह आर्कटिक का फुल कंट्रोल सेंटर बन सकता है। रूस लगातार आर्कटिक में नए सैन्य ठिकाने, नई पनडुब्बियां, नए एयरबेस और नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रूस पर नजर रखने का वॉच टावर है।

दुर्लभ खनिज

आज की दुनिया मोबाइल, चिप्स, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही है। इन सबकी जान हैं-रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बिना इनके आधुनिक तकनीक ठप हो जाती है लेकिन इन पर अभी चीन का दबदबा है। करीब 60झ70 प्रतिशत सप्लाई चीन से आती है। अमेरिका इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है और यहीं ग्रीनलैंड अहम हो जाता है। इस द्वीप की धरती के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा खजाना छिपा है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाता है, तो टेक्नोलॉजी की जंग में चीन को सीधी चुनौती मिल सकती है।

तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षा

दुनिया की ऊर्जा भूख खत्म नहीं हुई है। तेल और गैस अब भी वैश्विक राजनीति का ईंधन हैं। ग्रीनलैंड के आसपास समुद्र की गहराइयों में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। अभी बर्फ और मौसम खुदाई में रुकावट हैं लेकिन जैसे-जैसे आर्कटिक पिघल रहा है, ये संसाधन सुलभ होते जा रहे हैं। अमेरिका इसे भविष्य का ऊर्जा बैंक मानकर चल रहा है।

आर्कटिक सिल्क रोड

ग्लोबल वॉर्मिंग सिर्फ पर्यावरण संकट नहीं, यह भू-राजनीतिक बदलाव भी है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एशिया से यूरोप जाने के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो सकता है। इस रूट को कहा जा रहा है- आर्कटिक सिल्क रोड ग्रीनलैंड इस रास्ते का प्राकृतिक गेटवे है। जो इस रूट को कंट्रोल करेगा, वह वैश्विक व्यापार की दिशा तय करेगा। अमेरिका यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता।

चीन और रूस को रोकने की रणनीति

रूस आर्कटिक में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन निवेश के जरिए पैर जमा रहा है। चीन खुद को नियर-आर्कटिक स्टेट कहता है, भले ही उसका आर्कटिक से सीधा भौगोलिक रिश्ता न हो। ग्रीनलैंड में चीन ने एयरपोर्ट, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कोशिश की। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई तो उसका उत्तरी दरवाजा दुश्मनों के लिए खुल जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, रणनीतिक दीवार है।

अमेरिका की पुरानी चाहत

ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर नई नहीं है। 1867, 1910, 1946; तीन बार अमेरिका ने डेनमार्क को ऑफर दिया। 1946 में तो 100 मिलियन डॉलर का सोना तक देने को तैयार था। हर बार जवाब मिला झ ना लेकिन ट्रंप ने डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर सीधी ज़िद पकड़ ली-अगर खरीदा नहीं जा सकता तो दबाव डालो।

बिना डर के परीक्षाओं का सामना करें

● डॉ विजय गर्ग

यदि आप छात्र हैं और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बेचैन और घबराये हुए हैं, तो संभवतः आप चिंता और भय से ग्रस्त होंगे। आपको ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि आपको चिंता होती है कि आप अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाएंगे। लेटर टू ए स्टूडेंट नामक पुस्तिका में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने परीक्षा के डर की महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा की है।

उनका कहना है कि परीक्षा का डर छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके तनाव के कारण कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं। इस संदर्भ में 'परीक्षा बुखार' शब्द गढ़ा गया है। यहां तक कि जिन छात्रों ने लंबे समय तक अध्ययन किया है, वे भी परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। इसलिए, स्वामी कहते हैं, हिम्मत मत हारो, तुम निश्चित रूप से स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो। भय मनोविकृति से बाहर निकलने के लिए, स्वामी पुरुषोत्तमानंद छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वे स्वयं से पूछें कि डरने से उन्हें क्या लाभ होगा। क्योंकि, भय बीमारी लाता है। लेकिन साहसी और बहादुर होकर, एक औसत छात्र भी परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यदि कोई छात्र भय को दूर रखता है, तो यह उसके मन और शरीर की शक्ति से वंचित कर देगा। ₹इसका एकमात्र परिणाम यह हो सकता है: परीक्षा देते समय आप जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसे 'भूल' जाएंगे। यही डर आपको भ्रमित उत्तर लिखने के लिए मजबूर करता है।₹ वह कहते हैं, ₹आत्मविश्वास को अनुशासित अध्ययन के साथ मिलाकर अपने मन में छिपी भय की भावना को दूर करें; अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें... यह दृढ़ विश्वास कि आप परीक्षाएं अच्छी तरह से लिखेंगे, शांत मन के साथ, आत्मविश्वास है। यदि आप इसे विकसित कर सकें, तो भय गायब हो जाएगा और उसके स्थान पर उत्साह उभर आएगा।₹

छात्र स्वामी विवेकानंद के उत्साहवर्धक शब्दों से प्रेरणा ले सकते हैं, जिनका विश्वास की शक्ति पर बहुत विश्वास था। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे पहले अपने आप पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा: ₹दुनिया का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिनका अपने आप पर विश्वास था। वह विश्वास अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करता है। आप कुछ भी कर सकते हैं. आप तभी असफल होते हैं जब आप अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते।₹ विभिन्न अवसरों पर स्वामीजी ने इस बात पर जोर दिया कि ₹आप जो भी सोचेंगे, आप वही होंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर समझते हैं, तो आप कमजोर हो जायेंगे; यदि आप स्वयं का मजबूत मानते हैं, तो आपके पास ताकत होगी।₹ वह कहते थे: ₹कभी भी यह मत कहो कि, 'मैं नहीं कर सकता', क्योंकि तुम अनंत हो। यहां तक कि समय और स्थान भी आपके स्वभाव की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं।₹

विवेकानंद की सफलता के लिए नुस्खा यह है: ₹सफल होने के लिए, आपके पास जबरदस्त दृढ़ता और जबरदस्त इच्छाशक्ति होनी चाहिए। दृढ़ आत्मा कहती है, 'मैं समुद्र को पीऊंगा, मेरी इच्छा से पहाड़ टूट जाएंगे।' उस तरह की ऊर्जा, उस तरह की इच्छाशक्ति रखें; कड़ी मेहनत करें, और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे₹... उन्होंने आगे कहा: ₹यदि उप-निषादों में से कोई एक शब्द है जो अज्ञानता के लोगों पर बम की तरह फट रहा है, तो वह है निडरता... शक्ति जीवन है; कमजोरी मृत्यु है। शक्ति सुख है, जीवन शाश्वत है, अमर है; कमजोरी तनाव और दुख है...।₹

जो छात्र निडरता विकसित करते हैं, तथा परीक्षाओं का साहसपूर्वक सामना करते हैं, उनके लिए सफलता आस-पास ही प्रतीक्षा कर रही है। यह सच है कि कभी-कभी दुर्भाग्यवश, सबसे मेहनती और समर्पित छात्रों को भी परिणाम अच्छे नहीं लगते। हालाँकि, असफलता के सबसे बुरे परिदृश्य में भी आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया का अंत है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है कि हर काम में सफलता और असफलता होती है। वास्तव में, असफलताएं हमें और भी अधिक बुद्धिमान बनाती हैं। निरंतर अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, इसलिए किसी को भी प्रयास करते समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

₹कल एक और दिन है₹ के लिए नई आशाओं और अवसरों के साथ, और आपको नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की उम्मीद करनी चाहिए।

वाइफ स्वैपिंग

और हमारे रिश्तों की टूटती नींव: समाज का आईना

● डॉ प्रियंका सौरभ

कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर लिखना आसान नहीं होता। वे केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और नैतिक साहस की भी माँग करते हैं। यह विषय भी उन्हीं में से एक है, जहाँ चुनौती केवल प्रस्तुति की नहीं, बल्कि उस सच को सामने लाने की है जिसे समाज अक्सर ढककर रखना चाहता है। संस्कृति की आड़ में या आधुनिकता के नाम पर जिस चुपचाप गिरावट को स्वीकार किया जा रहा है, उस पर प्रश्न उठाना अब जरूरी हो गया है। आज जब परिवार की पवित्र संस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, 'वाइफ स्वैपिंग' जैसी प्रवृत्ति न केवल वैवाहिक बंधनों को चुनौती दे रही है, बल्कि पूरे समाज के मूल्यों को झकझोर रही है। ह्लवाइफ स्वप्पिंगह्व सुनते ही अधिकतर लोग इसे पश्चिमी संस्कृति या महानगरों तक सीमित मान लेते हैं। यह सोच हमें आत्मसंतोष देती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक असहज और व्यापक है। क्या यह प्रवृत्ति वास्तव में केवल बड़े शहरों तक सीमित है, या फिर इसकी छाया गाँवों और छोटे कस्बों तक भी पहुँच चुकी है—बस हम उसे देखने से बच रहे हैं? उत्तर प्रदेश, केरल और लद्दाख जैसे क्षेत्रों से सामने आए मामले बताते हैं कि यह समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर मौजूद है।

यह विषय सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के भीतर बदलते रिश्तों को समझने के लिए जरूरी है। यह विवाह संस्था की कमजोर होती नींव, रिश्तों में बढ़ती दरार और आधुनिकता के नाम पर मूल्यों की गलत व्याख्या की ओर ध्यान दिलाता है। यह केवल शारीरिक इच्छा का प्रश्न नहीं, बल्कि असुरक्षा, मानसिक अधूरापन, संवादहीनता और सामाजिक पाखंड का परिणाम भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसमें भावनात्मक शोषण, ईर्ष्या और विश्वास का पूर्ण विघटन होता है।

इस तरह के संवेदनशील विषय को संतुलित और मर्यादित भाषा में रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि गंभीरता बनी रहे। यह भी सामने आता है कि किस प्रकार सामान्य दिखने वाले परिवार धीरे-धीरे ऐसे कुचक्र में फँस जाते हैं, जहाँ रिश्ते भावनाओं की जगह समझौते और दिखावे का रूप ले लेते हैं। बैंगलोर, हापुड़ जैसे स्थानों से सामने आए मामले इसकी पुष्टि करते हैं।

आज यह मान लेना भूल होगी कि ऐसी प्रवृत्तियाँ केवल महानगरों तक सीमित हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जहाँ स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के नए रास्ते खोले हैं, वहीं मूल्यों के क्षरण को भी आसान बना दिया है। आभासी दुनिया में ह्लसामान्यह्व लगने वाली भाषा, व्यवहार और रिश्ते वास्तविक जीवन में परिवारों की नींव हिला रहे हैं। आईटी क्रांति, उपभोक्तावादी संस्कृति और पश्चिमी प्रभाव ने युवा वर्ग में प्रयोग की होड़ बढ़ाई है। आर्थिक असमानता, संयुक्त परिवार का विघटन और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता इसे बढ़ावा दे रही हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह यौन असंतोष, ईर्ष्या और रोमांच की तलाश से उपजता है।

भारतीय संदर्भ में यह पुरुषप्रधान समाज की देन है। पत्नियाँ डर के मारे चुप रहती हैं—तलाक का कलंक, आर्थिक असुरक्षा या परिवार का विघटन। सोशल मीडिया ग्रुप्स ने इसे संगठित रूप दिया है। टियर-2 शहरों में तकनीक-साक्षर युवा इसमें लिप्त हैं। इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। वैवाहिक स्तर पर विश्वास टूटता है, ईर्ष्या बढ़ती है, भावनात्मक लगाव नए पार्टनर से हो जाता है। बच्चों पर असर लंबे समय तक रहता है—वे असुरक्षा और रिश्तों की अस्थिरता सीखते हैं। विस्तारित परिवार समर्थन छोड़ देता है। समाज स्तर पर यह नैतिक क्षय और महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देता है। भारत में परिवार संरचना बदल रही है, लेकिन यह विकृति नई चुनौतियाँ ला रही है।

यह विमर्श केवल प्रश्न खड़े नहीं करता, बल्कि समाधान की ओर भी संकेत करता है। परिवार स्तर पर खुला संवाद, काउंसलिंग, भावनात्मक अंतरंगता आवश्यक है। समाज स्तर पर स्कूलों में नैतिक शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। कानूनी स्तर पर कढउ धाराओं का सख्त उपयोग, परिवार परामर्श नीतियाँ बनानी चाहिए।

यह विषय अश्लीलता नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह पाठक को असहज करता है, सोचने पर मजबूर करता है। शायद इसी असहजता में इसका सबसे बड़ा सामाजिक महत्व निहित है—कि हम अपने रिश्तों को पुनः परिभाषित करें। समय है जागने का।

परीक्षाएं

जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हैं

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचलन से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उससे संज्ञान का ह्रास हो रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है। विश्व में 5.66 अरब डिजिटल मीडिया प्रोफाइल हैं।

● संजय कुमार

भारत में छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाने के लिए शुरू हुई 'परीक्षा पे चर्चा' पहल आज एक बड़ी जन-भागीदारी बन चुकी है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छात्रों के बीच हुई एक बातचीत से आरंभ हुई यह पहल अब करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 2025 में इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया, जब एक ही महीने में 3.53 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी के लिए पंजीकरण किया। इसकी कुल पहुंच 21 करोड़ से अधिक दर्शकों तक रही, जिसमें विदेश स्थित भारतीय स्कूल भी शामिल थे। यह कार्यक्रम छात्रों को यह संदेश देता है कि परीक्षाएं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि सीखने की यात्रा का सिर्फ एक प्रमुख चरण हैं।

प्रधानमंत्री बार-बार इस पर जोर देते हैं कि परीक्षा केवल किसी विशेष क्षण में आपकी तैयारी को मापती हैं, जबकि सीखना लगातार और आनंददायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'आजीवन सीखने' की अवधारणा पर गहराई से जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य यह

है कि अंकों का प्रतिशत बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अलग-अलग कौशल सीखने, नई गतिविधियों को आजमाने और चुनौतियों को डर के बजाय अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जाना है।

इस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है। विशेषज्ञ छात्रों को तनाव कम करने के आसान तरीकों से परिचित करा रहे हैं, जिनमें 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक, पर्याप्त नींद, पानी, व्यायाम और ध्यान जैसी स्वस्थ दिनचर्या शामिल हैं। 5-4-3-2-1 इंद्रिय-आधारित ध्यान अभ्यास है, जिसे पांचों इंद्रियों का उपयोग करके विचारों की दौड़ को शांत करने और अंततः उन्हें एक इंद्रिय तक सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा करने से आपका ध्यान चिंता पैदा करने वाले विचारों से हटकर वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। इस तकनीक को 18वीं शताब्दी में बेट्टी एलिस एरिक्सन ने विकसित किया था। खेल जगत की कई हस्तियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया था कि खेल पढ़ाई में बाधा नहीं, बल्कि तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं।

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचलन से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उससे संज्ञान का ह्रास हो रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है। विश्व में 5.66 अरब डिजिटल मीडिया प्रोफाइल हैं। लोग प्रतिदिन डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर सामग्री देखने में 15 अरब घंटे व्यतीत करते हैं, जो मानव जीवन के 17 लाख वर्षों से अधिक के बराबर है। अत्यधिक उपयोग से 'डिजिटल डिमेंशिया' में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मस्तिष्क के उन क्षेत्रों मंअ ग्रे मैटर की कमी हो जाती है, जो भावनात्मक विनियमन और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम डिजिटल मीडिया को नकारने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें इसके उपयोग के

लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए।

तकनीकी विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे मोबाइल और डिजिटल साधनों को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि तकनीक मददगार बने, बोझ नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अभिभावकों को भी महत्वपूर्ण संदेश देता है कि वे बच्चों का ध्यान केवल अंकों पर न लगाएं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। बच्चों की तुलना दूसरों से न करें और अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे खुलकर अपने डर, चुनौतियों और उम्मीदें साझा कर सकें। अभिभावकों का सहयोगी व्यवहार बच्चों की परीक्षा तैयारी में सबसे ज्यादा मदद करता है।

भारतीय शिक्षा दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति को एक एकाकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साझा पथ माना गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षकों से अपील करता है कि वे रटने की संस्कृति से आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें छात्र-केंद्रित, तनाव-मुक्त और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की जरूरत है ताकि परीक्षाएं केवल याद्दाश्त नहीं, बल्कि समझ, अनुप्रयोग और विकास को माप सकें। डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग भी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

स्कूलों और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस पहल के सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए स्कूलों में वेलनेस कमेटियां बनाना, तनाव प्रबंधन और अध्ययन कौशल पर कार्यशालाएं आयोजित करना, अभिभावक-शिक्षक संवाद बढ़ाना और छात्रों की उपलब्धियों को केवल अंकों के बजाय विविध क्षेत्रों में पहचानना जरूरी बताया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभिलेखित एक्जाम वारियर्स जैसे संसाधनों को हर छात्र तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। अंततः परीक्षा पे चर्चा मात्र एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका संदेश स्पष्ट है-परीक्षाएं बोझ नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और खुद को समझने का अवसर हैं।

(लेखक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव हैं)

पड़ोसी मुल्क की 'बेईमानी' पर टीम इंडिया ने किया था वॉकआउट

ये 5 किस्से बताते हैं भारत-पाकिस्तान की अदावत की कहानी

भारत-पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट फील्ड पर जब उतरती हैं तो माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। जब 1970, 80 और 90 के दशक में भारत और पाकिस्तान की टीमें एकदूसरे के खिलाफ खेलती थीं तो खिलाड़ियों के बीच भी कई बार गहमागहमी देखने को मिलती थी। 1978 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में तो टीम इंडिया ने पड़ोसी मुल्क की बेईमानी से तंग आकर मैदान छोड़ने तक का फैसला लिया था और वॉकआउट कर दिया था।

भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर होने वाली बहसबाजी और लड़ाइयों के भी काफी किस्से हैं। गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों के समय में भी मैदान पर खूब लड़ाइयां देखने को मिलीं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ किस्सों पर प्रकाश डालेंगे जो बताते हैं कि क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच अदावत पुरानी है।

क्रिकेट से दूर राजनीतिक मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान दोनों देश हमेशा विपरीत दिशा में रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई युद्ध भी हुए। पाकिस्तान की ओर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के कारण भारत से उसके संबंध कभी सामान्य नहीं रहे। हाल ही में पहलगाम घटना, ऑपरेशन सिंदूर और अब बांग्लादेश के विश्व कप से बाहर होने के मुद्दे के कारण माहौल और गर्मा चुका है।

पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ खेलने से मना किया है। फिलहाल 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस है। इन सभी विवादों के बीच जानेंगे कि वे कौन-कौन से पल थे जब भारत और पाकिस्तान की टीमों और उसके खिलाड़ियों के बीच मैदान पर गहमागहमी देखने को मिली।

1978 में भारतीय टीम ने किया था वॉकआउट

नवंबर 1978 में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सात विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 37 ओवर्स में दो विकेट गंवाकर 183 रन बना लिए थे। मैच पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा था तभी विपक्षी टीम ने बेईमानी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी टीम को अंपायर्स (तब आईसीसी की ओर से तटस्थ अंपायर रखने का कोई नियम नहीं था) का भी साथ मिला।

उन दिनों एक ओवर में ना ही दो बाउंसर होती थी और ना ही वाइड को लेकर नियम सख्त थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जब देखा कि मैच उनके हाथ से निकल रहा है तब विपक्षी टीम के कप्तान ने 38वें ओवर में सरफराज नवाज को गेंद थमाई। सरफराज नवाज ने उस ओवर में अंशुमान गायकवाड़ को लगातार चार बांउसर फेंकी और अंपायर ने एक भी बॉल को वाइड नहीं दिया।

अंपायरों और पाकिस्तान को बेईमानी करता देख तत्कालीन भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी को गुस्सा आ गया। उन्होंने मैदान पर जाकर बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम में बुला लिया। इससे पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया। भारत ने सीरीज जरूर गंवाई, लेकिन आत्मसम्मान बरकरार रखा। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से बेईमानी की यह पहली घटना नहीं है। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले मल्टीनेशन टूर्नामेंट में भारत के साथ तटस्थ मैदान पर खेलने को लेकर एमओयू साइन किया, लेकिन अब उसका ईमान डोल गया।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुद्दे में बेगानी शादी में अब्दुल्लाह दीवाने की तरह बतने हुए हस्तक्षेप किया और सभी अनुबंधों के खिलाफ जाकर भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया, जबकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो में 15 फरवरी को खेला जाना है। कोलंबो का मैदान दोनों देशों के लिए न्यूट्रल वेन्यू है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान की

मेजबानी वाली चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर मुकाबला खेला था।

भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच मैदान पर हुईं लड़ाइयां

1- जावेद मियांदाद की मेंढक जम्प

1992 विश्व कप के मुकाबले में जावेद मियांदाद भारत के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान को 217 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने दो विकेट गंवा दिए थे। सचिन तेंदुलकर के हाथ में गेंद थी और भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे बार-बार अपील कर रहे थे। जावेद मियांदाद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ।

इसके बाद दोनों के बीच शब्दों के बाण चले। जावेद मियांदाद ने अंपायर से शिकायत भी की। अगली गेंद पर जब जावेद मियांदाद दो रन दौड़कर पूरे कर रहे थे तो किरण मोरे ने उनके खिलाफ रनआउट की अपील की। इस पर जावेद मियांदाद इतना चिढ़ गए कि वह पिच पर मेंढक की तरह कूदने लगे। उनकी इस जम्प का किस्सा खूब वायरल हुआ और आज भी याद किया जाता है।

2- जब वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल उलझे

1996 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जब चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, उसी वक्त भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सोहेल के बीच गहमागहमी देखने को मिली। पाकिस्तान 287 के लक्ष्य का पीछा कर रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका मारा और वेंकटेश की ओर देखते हुए अंगुली से इशारा किया।

इसको देख वेंकटेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी और सही समय का इंतजार किया। इंतजार का फल वेंकटेश के लिए मीठा था। वेंकटेश प्रसाद ने अगली ही गेंद पर आमिर सोहेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को उन्हीं के अंदाज में अंगुली दिखाते हुए पवेलियन लौटने का इशारा किया। यह वाकया काफी चर्चा का विषय बना। आज 30 साल बाद भी याद किया जाता है।

3- गौतम गंभीर-शाहिद अफरीदी की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच 2007 में कानपुर में खेले गए वनडे मैच के दौरान गौतम गंभीर और शाहिद आफरीदी एक दूसरे से भिड़ गए थे। उस वक्त हुआ यह था कि गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की एक गेंद पर चौका लगाया और अगली ही गेंद पर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े। रन लेते वक्त अफरीदी उनके रास्ते में आ गए और दोनों के बीच टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच जमकर नोंक-झोंक हुई थी।

4- गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच नोक-झोंक

2010 एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था, तभी भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल के बीच नोक-झोंक हुई। यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में था। सईद अजमल की एक गेंद गौतम गंभीर के बैट को मिस करते हुए विकेटकीपर कामरान अकमल के हाथों में गई। इसके बाद कामरान अपील करते-करते पिच तक आ पहुंचे।

हालांकि, अंपायर ने अपील को नकार दिया, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गंभीर और कामरान में झड़प हो गई। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के काफी करीब पहुंच गए थे। साथी खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ।

गौतम गंभीर वर्तमान में भारत के कोच हैं और एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नो हैंडशेक विवाद के बीच भी वह चर्चा में रहे थे। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तो गंभीर पर नजरें टिकी रहेंगी।

5- हरभजन सिंह-शोएब अख्तर में बहस

एशिया कप 2010 में भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच बहस का मुद्दा काफी गमार्या था। हरभजन ने शोएब के ऊपर छक्का लगाया था। इससे शोएब अख्तर खीज उठे और उन्होंने भज्जी को कुछ कहा। इसके बाद दोनों के बीच शब्दों के बाण चले। फिर जब मैच खत्म हुआ उस वक्त हरभजन ने जीत का जश्न आक्रामक तौर पर मनाया। उसके बाद शोएब ने इशारा किया और जाने को कहा।

4- गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच नोक-झोंक

2010 एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था, तभी भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल के बीच नोक-झोंक हुई। यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में था। सईद अजमल की एक गेंद गौतम गंभीर के बैट को मिस करते हुए विकेटकीपर कामरान अकमल के हाथों में गई। इसके बाद कामरान अपील करते-करते पिच तक आ पहुंचे।

हालांकि, अंपायर ने अपील को नकार दिया, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गंभीर और कामरान में झड़प हो गई। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के काफी करीब पहुंच गए थे। साथी खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ।

गौतम गंभीर वर्तमान में भारत के कोच हैं और एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नो हैंडशेक विवाद के बीच भी वह चर्चा में रहे थे। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तो गंभीर पर नजरें टिकी रहेंगी।

ईशा मालवीय

बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारियों में जुटी हैं

टीवी शो 'उड़ारियां' से फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। इस तरह की खबरें है कि टीवी पर अपना जलवा बिखेरने के बाद जल्दी ही वह एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म और प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स फिलहाल एक खास स्ट्रेटेजी के तहत गुप्त रखी गई हैं लेकिन अंदर के सूत्रों का कहना है कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं है बल्कि एक हाई-स्केल प्रोजेक्ट है।

रिपोर्टस के अनुंसार 'ईशा मालवीय जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह ईशा का बॉलीवुड में बड़ा डेब्यू साबित हो सकता है।

फिलहाल ईशा एक पंजाबी फिल्म 'इश्कां दे लेखे' की शूटिंग में बिजी है, जिसके व्दारा वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं।इस फिल्म में वो पंजाबी सिंगर और एक्टर गुरनाम भुल्लर के संग रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। मनवीर बराड़ व्दारा निर्देशित उनकी ये रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

पिछले कुछ दिनों से ईशा मालवीय के पब्लिक अपीयरेंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। फैंस तो जैसे उनकी अपीयरेंस और लुक पर मर ही मिटे हैं।

ईशा मालवीय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी नई-नई तस्वीरों से ऑडियंस को अपना मुरीद बना लेती हैं। हर बार ही वह अपने लुक्स और फैशन सेंस से ऑडियंस का दिल चुरा लेती हैं। फैंस उनकी हर एक अदा पर अपना दिल हार बैठते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश

ONE DISTRICT ONE CUISINE

व्यञ्जनेषु वसति संस्कृतिः

UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश दिवस (24 जनवरी, 2026) के अवसर पर

एक जनपद-एक व्यञ्जन योजना लॉन्च

- प्रदेश के हर जनपद के विशिष्ट व्यंञ्जनों को मिलेगी नई पहचान
- पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों, छोटे उद्यमियों को स्थायी आजीविका के अवसर

प्रगति की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

S.B. MOTORS

KISHANGANJ

ROYAL ENFIELD

प्रिय ग्राहक ...

किशनगंज रॉयल एनफील्ड द्वारा **एक नयी पहल**

अब आप घर बैठे अपनी Royal Enfield

मोटरसाइकिल की सर्विस करायें

घर और ऑफिस में रहकर

सर्विस का लाभ उठाएं

Open Time :-

9:00 a.m to 7:00 p.m

College Road (Near Imilgola Chowk) Paschimpally, Kishanganj

Contact Number :- Sales - 7281885566 | Service - 7281885544